

नई दिल्ली

गुरुवार

08 अक्टूबर 2026

वर्ष: 13, अंक: 35

पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु०

E-mail

story@sadbhawna.today

sadbhawnatoday@gmail.com

web: www.sadbhawna.today

लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन सुराज के शिक्षक...पेज-05

DELHIN/2014/58158

देश को विकसित बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो...**पेज-08**



हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना हुई

आवाज़ अधिकार की

एक नजर

सीजेपी और एआईएसए 10 अक्टूबर को जंतर- मंतर पर करेंगे प्रदर्शन

नई दिल्ली। काँग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) और अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसएफ) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विरोध गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मांगों को लेकर 10 अक्टूबर को यश के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और एआईएसएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बुधवार को प्रेस वलब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सौरव दास ने कहा कि सीजेपी, सभी छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेगी और चुनावी व्यवस्था में सुधार होने के बाद ही वापस लौटगी। उन्होंने कहा कि सरकार 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के खिलाफ साजिश रचने के बजाय, व्यवस्था में सुधार पर बातचीत के लिए युवाओं के प्रतिनिधिमंडल को वयो नई बुला सकती। उन्होंने सरकार पर विरोध प्रदर्शन को पटरी से उतारने और तनावपूर्ण एवं हिंसक माहौल बनाने का आरोप लगाया है। सौरव ने कहा कि एक लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहें। इससे को फर्क नहीं पड़ता कि वे हममें से कितनों को हिरासत में लेते हैं, याद रखें कि यह लड़ाई तो लड़नी ही है, चाहे हम हों या न हों। अगर वोट देने का हमारा अधिकार सुस्थित रहेगा, तभी हम अपने भ्रष्ट तंत्र को बदल पाएंगे। नेहा बोरा ने कहा कि 10 अक्टूबर को होने वाला प्रदर्शन हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हम अपनी अस्थिर सांस तक अपने लोकतंत्र को लिए लड़ेंगे और इसे कमजोर या खत्म करने की कोशिश करने वाली हर ताकत के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे।

मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति ने दी बधाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण पड़ाव जनता के कल्याण के प्रति उनके दृढ़ समर्पण तथा भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के संकल्प को दर्शाता है। मुर्मु ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हाल के वर्षों में देश में हुआ बदलाव लोगों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आवास, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, स्वरक्ष ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ संपर्क, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अवसरों को मजबूत करने वाली पहलों ने देशभर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि गरीबी कम करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति इस बदलाव के व्यापक और गहरे प्रभाव को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि दुनिया भारत को नए समानांतर और विविधता की नजर से देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और संकल्प से देश के लोग लाभान्वित होते रहे हैं और भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। मुर्मु ने प्रधानमंत्रियों को अच्छे स्वास्थ्य, सुखी और आने वाले वर्षों में निरंतर शक्ति की शुभकामनाएं दी तथा भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए उनके समर्थनों की सराहना की।

सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं मिला, यह हमारी ईमानदारी की पुष्टि: भगवंत मान

संगरूर, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की करीब 12 घंटे चली छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जांच एजेंसी की टीम में खाली हाथ लौटीं और उन्हें कुछ नहीं मिला।

उन्होंने इसे उनकी सरकार की ईमानदारी की पुष्टि बताया। श्री मान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हुए। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भाजपा विपक्षी नेताओं और उनके सहयोगियों की निशाना बनाती रही है। उन्होंने कहा

कि पंजाब राजनीति मुख्यमंत्री कहा कि राजनीति है और वह कोशिशों में नहीं है। भाजपा मां दावा वि

नई दिल्ली, ए.जे.सी। कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को यहां मुख्य चुनाव आयुक्त जॉनसेन कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तथा कुछ अन्य नेताओं के हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी और गठबंधन के कुछ अन्य नेताओं को मंगलवार को भी हिरासत में लिया गया था। गठबंधन के नेता आज प्रदर्शन के लिए बस में सवार होकर जंतर-मंतर जा रहे थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें पहले ही रोक दिया, जिसके बाद वे वहीं सड़क पर भी धरने पर बैठ गये। पुलिस ने कुछ देर बाद श्री गांधी तथा श्रीमती वाड्रा तथा अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी को पुलिस बाराखंबा रोड थाने ले गयी जहां से थोड़ी देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मंगलवार को दोनों नेताओं को किंग्सवे कैप पुलिस थाने में हिरासत में रखने के बाद देर रात रिहा किया गया था।

प्रदर्शन में आज भी इंडिया गलबन्धन के कई दलों के सांघद शामिल हुअ। मुख्य चुनाव आऑकत के इस्तीफा की मांग को लेकर ऑतर-ऑतर पड़ुऑन से पहले रोकऑ जाने के बाद सांघदों ने वहाँ पर धरना दिया। पुलिस श्री गांधी और श्रीमती वाइना को धरना स्थल से ऑबरन उऑकर ले गई। श्रीमती वाइना ने पहले हटने से इनकार किया और वह ऑमीन पर लेऑ गयीं। बाद में पुलिसकमी उन्हें ऑबरन उऑकर बारामंडी रोड पुलिस थाने ले गये। हिसऑत में लिये जाने के बाद श्री गांधी ने कहा, 'ऑनेश ऑमार के इस्तीफा देने तक प्रदर्शन नहीं रोकेंगा। हम तब तक प्रदर्शन नहीं रोकेंगे, जब तक ऑनेश ऑमार इस्तीफा नहीं देते। यह देश की सबसे पैऑर चीज की रक्षा की लड़ाई है। प्रऑधममंत्री नरेंद्र मोदी और गुजराती अमित शाह जो कऑर कर सकते हैं, करें, लेकिन वे हमें रोक नहीं सकते। हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई संविधान और ऑनता की आवाऑ की रक्षा के लिए है। तथा इसके लिए जिम्मेवर लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जायेगा। उन्होंने कहा, 'ऑल्मी जब-जब

शिवसेना विवाद पर शिंदे गुट ने कहा- 2011 के बाद पार्टी का कोई भी संविधान निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा गया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में शिवसेना विवाद मामले पर सुनवाई के दौरान बुधवार को एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शिवसेना के 2011 के संविधान के बाद कोई भी संविधान कभी निर्वाचन आयोग को सौंपा गया था। मामले पर कल भी सुनवाई होगी।

कौल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने खुद दो आदेशों में कहा है कि उसके पास पार्टी का जो एकमात्र संविधान मौजूद था, वह 2011 का संविधान ही था, जिसे निर्वाचन आयोग को सौंपा गया था। कौल ने दलील दी कि निर्वाचन आयोग ने खुद अपने दो आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि उसके पास पार्टी का जो एकमात्र वैध संविधान रिकॉर्ड में मौजूद था, उसी के आधार पर विचार किया गया। कौल ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट का यह कहना गलत है कि निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के संविधान के को सुनाव गुट के वरुण कहा कि और विधायी फैसला विन्यायाधीशों ने कि क्या चुनाव चिह्न मिलना अयोग्यता इस पर कौल कई फैसलें बहुतमें अवर्तित

राहुल, प्रियंका हिरासत में लिये जाने के बाद रिहा



नुबल करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा-चप्पा गूँज
 उठेगा इंकलाब के नारों से ।' श्रीमती वाझ ने कहा,
 'निर्वाचन आयोग से मिलने की मांग कर रहे सांसदों
 के साथ पुलिस ने मारपीट की। महिला पुलिसकर्मियों
 ने मुझे जमीन पर गिराया है और मुझे कई जगह खरोंचें
 आयी हैं। कुछ भी हो जाए, हम पीठे नहीं हटेंगे। जता
 के हक के लिए लड़ाई रहेंगे।' पुलिस द्वारा जब्त
 उठाए जाने पर श्रीमती वाझ ने कहा, 'ये कोई तरीका
 नहीं है। देखो देख रहा है... क्या हो रहा है। उन्होंने कहा
 कि हम लड़ाई केवल उनके बारे में नहीं, बल्कि
 निलोकोकतन के भविष्य के बारे में हैं। श्री गांधी और
 श्रीमती वाझ को हिरासत में लिया जाने पर प्रतिक्रिया
 व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
 कहा, 'चाहे कितने भी कंस कर दो, कितना भी
 डराने दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हमसे रहेंगे और आगे
 बढ़ते रहेंगे। एसआईआर के विरोध में पिछले दो दिन
 से चल रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान श्री गांधी और
 श्रीमती वाझ को दूसरी बार हिरासत में लिया गया।
 ममलवार को विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से

**मोदी सरकार के
संरक्षण में खाय जात है
महंगाई डायन : कांग्रेस**

नई दिल्ली । कांग्रेस ने दिवाली से पहले रस्ता पकड़ चुकी महंगाई को लेकर सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि बढ़ती कीमतों ने महंगाईवर्गीय तथा गरीब परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है और महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। कांग्रेस संघीय विभाजन के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर महंगाई की स्थिति को एक प्रचलित कहावत के जरिये बयान करते हुए कहा, 'मोदी सरकार के संरक्षण में महंगाई डायन खाद्य जात है। उन्होंने लोकन दिवाली खुशियां का त्योहार कहा कि बढ़ती कीमतों का रोगाहारी तथा गरीब परिवार का बजट बिगाड़ रहा है। दिवाली से पहले समाज के हर तबके को महंगाई का झटका लगा है। रमेश ने कहा कि सरकारी आंकड़ों से महंगाई को छिपाने की कोशिश हो रही है लेकिन यह दर्द हर भारतीय सह रहा है। कांग्रेस महासचिव ने सरकार से पूछा कि महंगाई पर राहत कम मिलेगी और आम परिवार की जेब पर पड़ रहे इस बोझ की जवाबदेही कौन लेगा।

मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष स्वर्णिम अध्याय: शाह

न गुरुग्राम, एजेंसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गुरुग्राम में सेवा संकल्प अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प व्योमिति यात्रा के शुभारंभ किया। साइबर सिटी के सिग्नेचर टावर के पास आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने यात्रा की मशाल मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी को साँपों और युवाओं से विकसित करने के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर उनके लाइव संबोधन को हजारों युवाओं और जनश्रितियों ने सुना। पीएम मोदी ने सेवा, जुशसन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए जगन्नागीदारी की अपील की। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का स्वर्णिम और युगांतकारी अध्याय हैं। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र में विशेष

महत्व रखता है। एक गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति ने अपनी क्षमता और प्रीतिभा से 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये 25 वर्ष इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएँगे। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने गरीबी उन्मूलन, अनुच्छेद 370 हटाने, नक्सलवाद की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। गरीब कल्याण योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी के 25 वर्ष गरीब कल्याण, भारत के गौरव और राष्ट्र की

पच्चीस साल की सेवा यात्रा व्यक्तिगत
महिमामंडन का अवसर नहीं, विकसित
भारत का संकल्प दोहराने का दिन: मोदी

नई दिल्ली, ए.जे.सी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात और केन्द्र सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को कहा कि यह यात्रा उनके लिए व्यक्तिगत महिमामंडन का अवसर नहीं, बल्कि देश के लिए एक संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यहां विकसित भारत संकल्प सभा में 2047 तक विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और का को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा, “हम करके रहेंगे... यी विल डू इट।” प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित लोगों ने भी इस नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ देशवासि मिलकर 2047 का विकसित भारत जरूर बनाएंगे और देश अब रुकने वाला नहीं है।



उन्के जीवन की कोई घटना व्यर्थ नहीं गई। प्रत्येक घटना ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। कोरोना महामारी ने उन्हें राष्ट्र की महत्त्व और सामूहिक शक्ति की चेतानी दी, जबकि गाँवों और गरीबों ने सिखाया कि साधन सीमित हो सकते हैं लेकिन सपने बड़े और हाँसले बुलंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों के सांस्कृतिक अनुभव वाले राष्ट्र की सेवा करते हुए उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने देश के करोड़ों स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को मनमन करते हुए कहा कि उन्के जीवन का ध्येय माँ भारती की निरन्तर सेवा है। ऐसे स्वयंसेवकों का उन्हें हमेशा भरपूर सहयोग मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 25 वर्ष की यात्रा को केवल अतीत की यादों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह दिन नए संकल्प लेने और उन वादों एवं इशारों की पूरा करने के लिए नई ऊर्जा जुटाने का है। उन्होंने कहा कि लाल किले से उन्होंने 'सबका प्रयास' की बात कही थी और आज की उई बुलाईयों पर पहुंचवाने के लिए इसी सामूहिक भावना की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने विकास भारत-2047, आत्मनिर्भर भारत और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने जैसे लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता लोगों की धमनियाँ में ऐसा आत्मविश्वास दौड़ रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता।

आरबीआई ने रेपो दर 0.25 प्रतिशत बढ़ाया, महंगा हो सकता है कर्ज

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक अस्थिरचतताओं के मद्देनजर बुधवार को अल्पवाधि कर्ज को अपनी नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इससे होम लोन, व्यक्तिगत ऋण और उद्योगों के लिए पूंजी की लागत बढ़ने की आशंका है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को आज सामान्य तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक पूंजी उपलब्ध कराता है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपना रुख भी बदल दिया है और अब बढ़ा धन्य है रेपो दर और बढ़ती की लिए तैयार है।

मल्होत्रा ने कहा कि निकट भविष्य में रेपो दर में कटौती की उम्मीद नहीं है। इसमें या तो वृद्धि होगी या इसे स्थिर रखा जाएगा। चालू वित्त वर्ष में एमपीसी



की यह चौथी और कैलेंडर वर्ष में पांचवाँ द्विमासिक बैठक थी जिसमें नीतिगत दरों की नियमित समीक्षा की जाती है। इस साल नीतिगत दरों में पहली बार बदलाव किया गया है पिछले साल एमपीसी ने चार बार में रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी जिससे आम लोगों को अपना घ

और वाहन खरीदने में काफी राहत मिली थी। आखिरी कटौती दिसंबर में (0.25 प्रतिशत) की गई थी। फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो दर बढ़ाई गई है। कोविड काल में मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच छह बार में इसमें कुल 2.5 प्रतिशत (250 आधार अंकों) की वृद्धि की गई थी।

प्रति के 25 वर्ष हैं और इसी को यादगार बनाने के लिए यह सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मशाल युवाओं को सौंपते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। यात्रा को शुभारंभ विकसित भारत सभा से हुआ, जिसमें हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवाओं, कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा करते हुए सिमनेर टावर के पास यात्रा की मशाल स्थापित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश-प्रदेश का विकास तभी सार्थक होगा, जब हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचें और जीवन सुखी-समृद्ध बने। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, युवा अधिकारिता मंत्री गौरव गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी, भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य डॉ. सुधा यादव, विधायक तेजपाल तंवर, यमला चौधरी, मुकेश शर्मा मौजूद रहे।

दिल्ली विस में राष्ट्रीय पर्यावरण बाल संसद का आयोजन

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में बुधवार को राष्ट्रीय पर्यावरण बाल संसद का आयोजन किया गया। इसमें 'आज बोएंगे, कल बढ़ाएंगे' विषय पर आयोजित इस बाल संसद में 7 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने विधानसभा के सदन में बैठकर पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास और जिम्मेदार नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हमारे बच्चे जिस भविष्य में जीवन बिताएंगे, वह इस बात से तय होगा कि हम आज क्या बचाते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ या तो हमारे द्वारा संरक्षित प्राकृतिक संसाधनों के लिए हमें धन्यवाद देंगी या फिर इस बात पर सवाल करेंगी कि हमने क्या-क्या नष्ट होने दिया।

बाल संवाद की कार्यवाही की सरादना करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बच्चों ने उस भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके साथ किसी विधानमंडल को कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानमंडल अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस अपेक्षा के साथ सदन में भेजते हैं कि जनिहित के विषयों पर निर्णयों, तथ्यों और तर्कों के साथ चर्चा होगी। बाल संवाद में बच्चों द्वारा की गई चर्चा न केवल युवाओं के लिए, बल्कि देश के सभी विधानमंडलों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बाल संवाद, तर्क और विचारपूर्ण चर्चा का मंच होता है। आज हमने यहां देखा कि सार्थक विचार-विमर्श को लोकतंत्र की लीकन मजबूत बना सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल अपनी बात रखने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनना, प्रश्न करना, समझना और तर्कपूर्ण संवाद के माध्यम से असहमति व्यक्त करना और तर्कपूर्ण संवाद के माध्यम



से समाधान तक पहुँचना भी लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। कार्यक्रम के केंद्रीय विषय पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख करते हुए विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण कोई सीमित या केवल नीतिगत विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के अस्तित्व से सीधे जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की रक्षा का सीधा संबंध उस हवा से है, जिसमें हम सांस लेते हैं। इसी प्रकार पानी के बिना जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती। प्रदूषित हवा, लगातार घटता हरित क्षेत्र और बढ़ती जल समस्या को न समझना मानवता के सामने खड़ी बड़ी चुनौती को न पहचानना है। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान पड़ोश के कार्य वह तब करेगे कि अपने वाली पौधियों को कैसे वातावरण मिलेगा। गुप्ता ने इस

धारणा को खारिज किया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास एक-दूसरे के विरोधी हैं।

उन्होंने दिल्ली विधानसभा द्वारा कागजरहित कार्यप्रणाली, डिजिटल व्यवस्था और सौर ऊर्जा के उपयोग को दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि हम सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं तो यह भी विकास है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा को अपनी विकास यात्रा भी 'विकास और विकास' को साथ लेकर आगे बढ़ने को दिशा में है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को नई तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाओं को अपनाया चाहिए, लेकिन इसके साथ उन्हें अपनी पहचानसिद्ध विकास के प्रति भी सजग रहना चाहिए। विधानसभा

के सदन में बैठे बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सदन सी वर्ष से अधिक लंबा चल रहा है। इतिहास का साक्षी रहा है। उन्होंने विद्वत्भाषा पढ़ते के योगदान, औपनिवेशिक काल की महत्वपूर्ण बहसों और रॉलेट एक्ट के विरोध से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह भारत केवल एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि भारत का लोकतांत्रिक यात्रा का जीवंत साक्षी है। यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य का निर्माण करते समय हमें अपने अतीत से मिले अनुभवों और सीख को कभी नहीं भूलना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाल संसद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बच्चों को केवल विधानसभा देखने का अवसर नहीं मिला, बल्कि उन्हें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही का अनुभव करने, अपनी राय रखने, अलग-अलग विचार सुनने और लोकतांत्रिक संवाद की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण बाल संसद जैसे कार्यक्रम बच्चों में ऐसी पीढ़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण को किसी एक दिन या अभियान तक सीमित न मानकर निरंतर नागरिक जिम्मेदारी के रूप में देखे। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयोजक गोपाल आर्य और सह-संयोजक राकेश जैन भी उपस्थित रहे। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि जब बच्चे पर्यावरण और समाजजनिक दायित्व से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार और संवाद करते हैं, तो वे भविष्य के प्रति हमारा विश्वास को और मजबूत करते हैं।

अब बैंकों को बताना होगा कितने सूचित जाति के लोगों को मिला कर्ज

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की पहल के बाद अब बैंकों को यह बताना होगा कि सरकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के कितने लोगों को कौज और दूसरी आर्थिक मदद दी गई है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बैंकों को निर्देश जारी किए हैं।

एनसीएससी के सचिव विवेक कुमार देवांगन ने 24 सितंबर 2026 को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि बैंकों की रिपोर्ट में यह जानकारी नहीं दी जा रही थी कि सरकारी योजनाओं का कितना लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिला। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वीनथि, सीजीटीएमएसई और एमएसएमई ऋण जैसी योजनाएं शामिल हैं। आयोग ने कहा था कि यह जानकारी जरूरी है। इससे पता चलेगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है। इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग ने 5 अक्टूबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए। अब बैंकों को हर योजना के तहत अनुसूचित जाति के कितने लोगों को मदद मिली, इसकी जानकारी देनी होगी। यह भी बताया होगा कि कुल लाभार्थियों में अनुसूचित जाति के लोगों



की संख्या और प्रतिशत कितना है। यह जानकारी देनी और बैंक के हिसाब से अलग-अलग योजनाओं के प्रतिशत देनी होगी। यह जानकारी नियमित रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ साझा करनी होगी। 19 अक्टूबर 2026 तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि बैंक और राज्य स्तरीय बैंक समितियाँ अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बता रही थीं कि मुद्रा लोन, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का फायदा कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को मिला। बिना इस आंकड़े के हम यह नहीं जान सकते कि एसीसी समुदाय को सही तरीके से मदद मिल रही है या नहीं। संविधान हमें यह जॉचने का अधिकार देता है। इस पर वित्तीय सेवा विभाग ने तुरंत सभी राज्यों के एएसएलबीसी को आदेश दिया कि अब से हर रिपोर्ट में साफ-साफ लिखें कि कितने एसीसी लोगों को काफ़ी प्रतिशत कितनी योजनाओं का लाभ मिला।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: आरोपित वीवो अधिकारी को बैंकोंक जाने की इजाजत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के वरिष्ठ अधिकारी हरबिंदर दहिया को आध्यात्मिक कारणों से 12 से 15 अक्टूबर तक बैंकॉक (थाईलैंड) जाने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश सचिन दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी एलआउट सर्वकृपर को इस चार दिवसीय यात्रा के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने यह अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि जांच में सहयोग और देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए दहिया पर कड़ी शर्तें लागू रहेंगी। उन्हें यात्रा पर जाने से पहले एक तिग राशि का बेल बॉन्ड और सफाईपत्रिजा कमा करनी होगी। यह पूरा मामला साल 2022 से चल रहे विवाह मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। ईडी

ने वीवी और उससे जुड़े लोगों पर जुलाई 2022 में देशभर के 48 स्थानों पर छापे मार था। ईडी ने वीवी को कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापे मार था। ईडी का दावा है कि छापे के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। इस मामले में कई चीनी नागरिक और भारतीय कंपनियाँ शामिल हैं। ईडी के मुताबिक करीब 62476 करोड़ रुपये की रकम वीवी ने गैरकानूनी रूप से चीन ट्रांसफर की थी। ये रकम भारत में टैक्स से बचने के लिए चीन ट्रांसफर की गई थी। इस सिलसिले में ईडी ने कई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में दिसंबर 2023 में हरबंदर दहिया, अंतरिम चीनी सीईओ होंग जुक्वान और टैक्स सलाहकार हेमंत मुंजल को गिरफ्तार किया गया था।

न्यू सीमापुरी में चार मंजिला इमारत गिरी, बच्चे समेत 7 घायल

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सोमापुरी इलाके ई-ब्लॉक में बुधवार को चार मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 3 साल के एक बच्चे समेत कुल 7 लोगों को मलबे से अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा ई-ब्लॉक स्थित मकान नंबर ई-401 में हुआ। करीब 25 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी इस इमारत के गिरने से आसपास की दो इमारतों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा।

सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंची। प्रभावित हिस्से से अब तक 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, इनमें करीब 3 साल का एक बच्चा भी शामिल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजे जाने की जानकारी है। पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमों मौके पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका को देखते हुए इलाके में गांघ की जा रही है। फिलहाल हादसे में इमारत जिनके की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस के मुताबिक, घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं।



आआपा ने मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में किया प्रदर्शन, 10 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आआपा) ने बुधवार को कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आआपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 10 अक्टूबर को देशव्यापी विविध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका मुख्य केंद्र जंतर-मंतर रहेगा। उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन का आह्वान 'कांफेरोच जनाता पार्टी' ने किया है और आआपा इस आह्वान का समर्थन कर रही है। उनके मुताबिक, 'वामपंथी दलों, छात्र संगठनों तथा कई अन्य छोटे-बड़े संगठन भी आंदोलन के समर्थन में हैं'।

बुराई से आआपा विधायक संजीव झा ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विषल लगातार सवाल उठता रहा है। संजीव झा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कथित तौर पर वोटों की चोरी के जरिए सरकारें बनाई गईं और चुनावी अनियमितताओं के माध्यम से सत्ता में आए लोगों



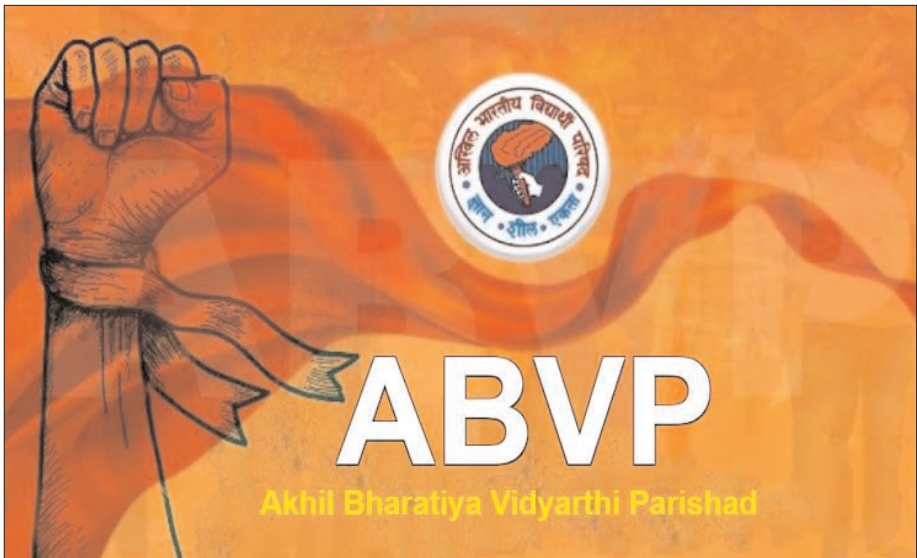
ने गैर-कानूनी सरकारें बनाई हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें देश को गुमराह करने के लिए जवाब देना चाहिए। आआपा विधायक ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि उसकी अनुमति के बिना फॉर्म-6 में बदलाव किए गए। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि ऐसे बदलाव क्यों किए

गाए और क्या इसके पीछे किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की कोशिश थी। प्रदर्शन के दौरान झा ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे पर आगे आ रहे हैं और विपक्षी दल चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में हुए कथित बदलावों पर स्पष्टीकरण देने और ज़िम्मेदारों तय करने की मांग की।

अभावविष के आंदोलन का असर, डीयू में 7 से 9 अक्टूबर तक फिर खुलेगी माइग्रेशन विंडो

नई दिल्ली, एअरसे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दिल्ली द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की माइग्रेशन संबंधी समस्या को लेकर लगातार उठाई जा रही मांग के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने माइग्रेशन विंडो को पुनः खोलने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय के अनुसार विद्यार्थी 7 से 9 अक्टूबर तक माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

अभाविप समर्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के निर्विवाचित प्रतिनिधि पिछले कई दिनों से डीन स्टूडेंट्स वेल्फेयर एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष माइग्रेशन प्रक्रिया को ठीक करने के पुनः खोलने और सौकी अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। परीक्षा परिणाम में देरी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी निश्चित समय-सीमा के भीतर माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए इस प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष लगातार अर्पणें मांग रखी। मांग पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद 6 अक्टूबर को अभाविप कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में आंदोलन किया और प्रशासन के समक्ष माइग्रेशन विंडो को दोबारा खोलने की मांग मजबूती से रखी। आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में



माइग्रेशन विंडा को 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए पुनः खोलने का निर्णय लिया है। अभावपि ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विद्यार्थियों की आवाज और संघर्ष की जीत बताया।

है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष यश ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर डूसू लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखता रहा है। माइग्रेशन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद बड़ी

संख्या में विद्यार्थी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। विद्यार्थियों की इस समस्या को देखते हुए प्रशासन से माइग्रेशन विंडो पुनः खोलने और अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी। 6 अक्टूबर के आंदोलन के बाद 7 से 9 अक्टूबर तक माइग्रेशन विंडो पुनः खोलने का निर्णय विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम है।

अभाषिपि दिल्ली मंत्री सायक शमा ने कहा कि
हिला भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के
अहित और अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है।
माइग्रेशन विंडो को पुनः खोलने की मांग भी विद्यार्थियों
की वास्तविक समस्या को ध्यान में रखते हुए लगाता।
प्रशासन के समक्ष रखी जाई। मांग पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं
होने के बाद 6 अक्टूबर को अभाषिपि कार्यकर्ताओं एवं
विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में आंदोलन किया।
इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 7 से 9 अक्टूबर
तक माइग्रेशन विंडो पुनः खोलने का निर्णय स्वागत योग्य
है। अभाषिपि ने सभी संबंधित विद्यार्थियों से अपील की कि
कि वे 7 से 9 अक्टूबर के बीच माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर
इस अवसर का लाभ उठाएं। संगठन ने कहा कि विद्यार्थियों
से जुड़े किसी भी मुद्दे पर वह उनके साथ खड़ा रहेगा और
आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन के समक्ष मजबूती से उनकी
आवाज उठाता रहेगा।

को विरोध-प्रदर्शन के दौरान बाँड़ी कैमरा पहनने का निर्देश देने से इनकार किया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भीड़ को काबू करने या विरोध-प्रदर्शन को संभालने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों के लिए हमेशा बाँड़ी कैमरा पहनने का निर्देश देते से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन चानुसुदेव साम्ब की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि वो इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लें। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले पर एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के बारे में छल्ला नहीं के भीतर फैसला ले। न्यायालय ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सरकार को कार्रवाई न करने से असंतुष्ट हैं, तो वे दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेशेवर वकील अखिल सिब्बल ने न्यायालय से सरकार को कार्रवाई करने के लिए एक समय देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने कहा कि जब किसी तरह की निगरानी की बात आती है, तो ज्यादातर मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जब यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप्रकार को बोझ को समझ सकते हैं। याचिका चाहत रायच ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान याचिकाकर्ता वहाँ मौजूद था। इस प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई, जिसमें छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों के घटनाएं शामिल हो गए। याचिकाकर्ता का कहना था कि औरतों पर जलूस से न्याया बल प्रयोग किया गया। इस दौरान लाठीचार्ज, पैलेट गन से लगी चोटें और एक महिला प्रदर्शनकारी को अधिकारी द्वारा थपड़ मारने की घटनाएं शामिल हैं। ये सभी वीडियो सरकारी एजेंसियों की ओर से रिकॉर्ड करने के बजाय आस-पास मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किए थे। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस का मौजूदा प्रस्टम्ट पीपी टी से बाहरी वीडियोग्राफरों पर निर्भर है, जो इलाके के बाहरी क्षेत्रों में तैनात होते हैं।

हाई कोर्ट ने दिल्ली में इमारतों के सुरक्षा ऑडिट से जुड़े कानूनी ढांचे पर स्पष्टता मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और समय-समय पर होने वाले ऑडिट से जुड़े कानूनी ढांचे के बारे में स्पष्टता मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन खान्ने ने साब्री की अथिथता वाली बेंच ने सत्य निकेतन जैसी घटनाओं में गिरफ्तार करते हुए प्राधिकारों से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। नई दिल्ली में सत्य निकेतन ट्रस्ट की याचिका में लगातार इमारतों के गिरने पर चिंता जताते हुए संरचनात्मक एवं आग से सुरक्षा के समयबद्ध एवं समग्र उपायों पर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। सत्य निकेतन इमारत गिरने का हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें मलबे में कई छात्र मर चुके थे। उसके बाद 7 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत के अचानक भरपूर गिरने के मामले को उच्च-स्तरीय जांच करेगा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में संश्लेषण करेगी और जांच के काम में तेजी लाए। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले को जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कहा था कि इस हादसे की जिम्मेदारी को जांच। न्यायालय ने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या किया गया ? ये न्यायालय को सूचित करें।

संवैधानिक आज़ादी के मायने कानूनी आज़ादी नहीं

सी. कुरैशी

कई महीनों से, मतदाता सूची में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ यानी एसआईआर ने मतदाताओं को परीक्षा में डाल रखा है। सोमवार को, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्रीय चुनाव आयोग के फ़ैसले लेने के तौर-तरीके पर सवाल उठे। न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जो इन खबरों से जुड़ी थीं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के नाम पर लिए गए फ़ैसलों या कामों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां जताईं थीं। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की मांग की। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करके सही किया कि केवल अख़बार की खबरों के आधार पर और एकतरफ़ा तौर पर ऐसा असाधारण कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि आयोग के फ़ैसले आम सहमति से हों; जहां आम सहमति संभव न हो, वहां निर्णय बहुमत के आधार पर हो। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अगर रिकॉर्ड से पता चलेगा कि कुछ निर्णय विशेष इस नियम के उलट लिए गए थे तो अदालत उन पर रोक लगा सकती है, उन्हें अधिकार-क्षेत्र से बाहर घोषित कर सकती है। अब एक नोटिस जारी किया गया है—विसंगति साबित करने में संबंधित लोगों का पक्ष सुना जाए। लेकिन विवाद का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अब सवाल सिर्फ़ यह नहीं रहा कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशासनिक रूप से सुस्पष्ट है। इससे भी पहले एक सवाल उठता है : क्या कुछ विवादित काम कानूनी तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के फ़ैसले थे भी या नहीं? 2023 के कानून की धारा 18 स्पष्ट है। इसका मुख्य कामकाज आम सहमति से होना चाहिए; जहां पर आयुक्तों की राय अलग-अलग हो, तो फ़ैसला बहुमत के आधार पर लिया जाए। यह सिद्धांत ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों’ से भी पुराना है (संदर्भ : नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम)। मुख्य चुनाव आयुक्त एक अध्यक्ष हैं, न कि एक कमांडर। सर्वोच्च न्यायालय ने टीएन शेषन मामले में भी यही कहा था। तीन सदस्यों वाली संवैधानिक संस्था में, दो सदस्यों की एक जैसी राय ही बहुमत है। किसी सामूहिक संस्था के भीतर मतभेद होना सामान्य है, यहां तक कि जब सब ‘ठीक’ हो। जो चीज मायने रखती है, वह यह कि बाद में क्या होता है। अगर आयुक्त ‘अ’ कोई एक प्रस्ताव रखता है और बाकी दो ‘भिन्न राय’ दर्ज करते



हैं, तो ‘अ’ के प्रस्ताव को ‘केंद्रीय चुनाव आयोग’ का फ़ैसला नहीं कहा जा सकता।

फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत एक कानूनी प्रपत्र है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के हवाले से आई रिपोर्ट से पता चला कि आयुक्त जोशी ने मई में एक प्रशासनिक निर्देश के जरिए एसआईआर की ज़रूरतों में अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। यह कहकर कि कानूनी फ़ॉर्म में बदलाव के लिए पहले नियमों में संशोधन की ज़रूरत है। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू भी इससे सहमत थे। फिर भी, बदली हुई ऑनलाइन प्रक्रिया ईसीआई नेट पर दिखाई दी। सोमवार को मामला नए मोड़ पर पहुंचा, जब फ़ॉर्म 6 में बदलाव का मुद्दा उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने साफ़ किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अनुमोदन नहीं किया था। यह भी कि अदालत इस बात की जांच करेगी कि ‘किसने क्या बदलाव किया है’। अब यही

सवाल केंद्र में हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ‘फॉर्म 6’ ने एक और दिलचस्प भूमिका ले ली है। आयोग ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कि वे पुरानी और संशोधित वोटर लिस्ट की तुलना करें। फिर उन पात्र मतदाताओं की पहचान की जाए, जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्हें फिर से शामिल करने में मदद करें। यह सुधारात्मक कदम बहुत अच्छा है। लेकिन जिस मतदाता का नाम 10, 20 या 30 साल से वोटर लिस्ट में था और एसआईआर के दौरान हटाया गया, उसे ‘नए’ मतदाताओं के लिए बने फॉर्म का इस्तेमाल करने और यह झूठा बयान देने के लिए क्यों और कैसे कहा जा सकता है कि वह पहली बार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है—नियमों के अनुसार ऐसा अपराधिक कृत्य है, जिसमें एक साल तक जेल की सजा हो सकती है? सूची से

हटाया गया मतदाता नया मतदाता नहीं होता। उसे लिस्ट में वापस शामिल किए जाने की ज़रूरत है, न कि पहली बार पंजीकरण की। अगर मौजूदा फॉर्म इसके लिए सही नहीं हैं, तो नियमों में बदलाव करके एक नया फॉर्म बनाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल का मामला बड़ा संस्थागत सवाल खड़ा करता है। जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के जरिए 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद, खबरों के अनुसार 22.21 लाख लोगों ने नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की गयी है। इसके अलावा, 16.10 लाख अपीलें वे मिलीं, जिनमें उन नामों को चुनौती दी गई, जो मतदाता सूची में शामिल किए गए। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू ने फाइल पर पूछा था कि ‘केंद्रीय चुनाव आयोग’ की ओर से यह अपीलें दायर करने के लिए कौन अधिकृत था? सवाल का पूरा जवाब मिलना चाहिए। गोवा का मामला भी ऐसा ही है, जहां मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारियों

ने 97 मतदाताओं को लिस्ट में वापस शामिल किए जाने के योग्य पाया, लेकिन केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित सॉफ्टवेयर ने अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले उन्हें वापस शामिल करने की इजाज़त नहीं दी। सॉफ्टवेयर कानूनी अधिकारियों के फैसलों से ऊपर नहीं हो सकता। ईसीआई नेट एक समानांतर चुनाव अधिकार संस्था नहीं बन सकता।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 26 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति में कई सुधारों की घोषणा की है : बैठकों से पहले एजेंडा बताया जाएगा, फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, आईटी टीमों द्वारा किए गए बदलावों की संस्थागत स्तर पर जांच होगी, चुनाव आयुक्तों के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। ईसीआई नेट को चुनावी कानूनों के अनुरूप बनाने पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन हर सुधार अतीत के बारे में एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे सुरक्षा उपाय पहले से स्वचालित क्यों नहीं थे? केंद्रीय चुनाव आयोग का यह कहना है कि उसके फ़ैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और राय में भिन्नता भी चर्चा का एक अंग होती है। इसीलिए अपनी इस बचाव मुद्रा को अब रिकॉर्ड से साबित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर पहले से कोई राय नहीं बनाई है। यानी फाइलों को सच बताने दें। भारत को एक पारदर्शी संस्थागत बही-खाते की ज़रूरत है : आयोग के सामने क्या प्रस्ताव रखे जाए, उसे किसने मंजूरी दी, किसने असहमति जताई, अंत में क्या फ़ैसला हुआ और किसके अधिकार से उसे लागू किया गया। नि:संदेह, केंद्रीय चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संवैधानिक आज़ादी का मतलब कानून से आज़ादी नहीं है। वह संस्था जो चुनावी कानूनों का पालन करने की मांग करती हो, उसे खुद भी मिसाल पेश करने वाला आचरण दिखाना चाहिए। नि:संदेह, चुनाव आयोग व्यक्ति न होकर एक संस्था है। इसकी विश्वसनीयता दशकों में उन आयुक्तों, अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओं ने बनाई है, जिन्हें भरोसा था कि अंपायर अपने ही नियमों का पालन करते हैं। नि:संदेह, एक बात पर किसी फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है: संसद ने तीन सदस्यों वाला आयोग बनाया है और यह तय किया है कि असहमति होने पर फ़ैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। वहां एक व्यक्ति खुद अपने आप में संस्था की जगह नहीं ले सकता। जब कोई कार्रवाई मतदाता और चुनाव आयोग के नाम पर की जाए, तो लोकतंत्र एक सरल सवाल पूछने का हकदार है : फ़ैसला किसका था?

आनुवंशिकता, वातावरण और जीवन-अभिव्यक्ति के अध्ययन ने यह समझने का रास्ता जरूर खोला है कि जीवन के अनुभव जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक पीढ़ियों के बीच जैविक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से ‘पूर्वजों के डीएनए पैटर्न की हीलिंग’ को वैज्ञानिक सिद्ध तथ्य के बजाय एक विचारारामक रूपक के रूप में समझना अधिक उचित होगा। जल और भावनाओं के संबंध की चर्चा में जापानी लेखक और शोधकर्ता मसारु इमोटो का नाम अक्सर लिया जाता है। हालांकि उनके निष्कर्षों को मुख्यधारा के वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर भी भारतीय तर्पण परंपरा को समझने में जल का प्रतीकात्मक महत्व इससे कहीं पुराना है। भारतीय चिंतन में जल केवल भौतिक पदार्थ नहीं, जीवन और चेतना की यात्रा का प्रतीक भी रहा है। इसलिए तर्पण के समय जल अर्पित करने को ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया मान सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अतीत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है व अपना वर्तमान उस परंपरा से जोड़ता है। श्राद्ध का सबसे बड़ा परिवर्तन शायद हमारे भीतर होता है। जब कोई श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, तो वह स्वयं अपने जीवन को देखने लगता है कि जीवन केवल ‘मैं’ तक सीमित नहीं है। मेरे भीतर मेरे माता-पिता हैं। मेरे माता-पिता की जीवन-कथा है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं को एक लंबी जीवन-शृंखला की कड़ी के रूप में देख सकता है।

पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का अवसर

गणेश कला

श्राद्ध और तर्पण को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, स्मृति, कृतज्ञता और पीढ़ियों से मिले संस्कारों को समझने की एक भारतीय दृष्टि के रूप में भी देखा जा सकता है। हमारे जेहन में शायद अपने पूर्वजों के नाम, गांव, कुछ पारिवारिक घटनाओं और उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां ही हैं। लेकिन हमारी सोच, व्यवहार, डर, आदतें और जीने के कुछ तरीके भी पिछली पीढ़ियों से हम तक पहुंचे हो सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक, हमारी जैविक संरचना में डीएनए की अहम भूमिका है। हमें अपने माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री मिलती है और इस तरह जैविक निरंतरता पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है। वहीं शोधों में सामने आया कि जीन की अभिव्यक्ति पर माहौल, जीवनशैली और अनुभवों का प्रभाव पड़ सकता है। इसे समझने को एपिजेनेटिक्स अहम क्षेत्र है। यहीं से भारतीय परंपरा में पूर्वजों के स्मरण व श्राद्ध-तर्पण को देखने का नया रास्ता खुलता है। मानव शरीर का बड़ा हिस्सा जल से बना है। भारतीय दर्शन ने जल को पंचमहाभूतों में स्थान दिया। वहीं तर्पण में जल अर्पित करने में गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है—“मैं अपने अस्तित्व की उस धारा को स्वीकार करता हूँ, जो मुझसे पहले भी थी और मेरे बाद भी आगे जाएगी।” जल अर्पित करते समय व्यक्ति पूर्वजों का नाम लेता है। अपने अतीत को याद कर स्वीकार करता है कि उसका वर्तमान अकेले उसने नहीं बनाया। यह प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। कई भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते। किसी पूर्वज के प्रति कृतज्ञता, पुराने पारिवारिक दुःख की याद या पीढ़ियों से चली आ रही अनकही कहानी-इन सबका हमारे मन पर प्रभाव हो सकता है। श्राद्ध व्यक्ति को उन भावनाओं को देखने और स्वीकार करने का अवसर देता है। हम केवल अपना वर्तमान लेकर पैदा नहीं होते। हमारा व्यक्तित्व परिवार, समाज, संस्कार, वातावरण और अनुभवों से बनता है। परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही कुछ आदतें और व्यवहार भी अगली पीढ़ियों में दिख सकते हैं। लेकिन इसे सीधे यह कहना कि ‘पूर्वजों की स्मृतियां डीएनए में रिकॉर्ड होकर उसी रूप में हमारे भीतर चलती हैं’, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। डीएनए और व्यवहार के बीच संबंध कहीं अधिक जटिल है।

आनुवंशिकता, वातावरण और जीवन-अभिव्यक्ति के अध्ययन ने यह समझने का रास्ता जरूर खोला है कि जीवन के अनुभव जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक पीढ़ियों के बीच जैविक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से ‘पूर्वजों के डीएनए पैटर्न की हीलिंग’ को वैज्ञानिक सिद्ध तथ्य के बजाय एक विचारारामक रूपक के रूप में समझना अधिक उचित होगा। जल और भावनाओं के संबंध की चर्चा में जापानी लेखक और शोधकर्ता मसारु इमोटो का नाम अक्सर लिया जाता है। हालांकि उनके निष्कर्षों को मुख्यधारा के वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर भी भारतीय तर्पण परंपरा को समझने में जल का प्रतीकात्मक महत्व इससे कहीं पुराना है। भारतीय चिंतन में जल केवल भौतिक पदार्थ नहीं, जीवन और चेतना की यात्रा का प्रतीक भी रहा है। इसलिए तर्पण के समय जल अर्पित करने को ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया मान सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अतीत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है व अपना वर्तमान उस परंपरा से जोड़ता है। श्राद्ध का सबसे बड़ा परिवर्तन शायद हमारे भीतर होता है। जब कोई श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, तो वह स्वयं



अपने जीवन को देखने लगता है कि जीवन केवल ‘मैं’ तक सीमित नहीं है। मेरे भीतर मेरे माता-पिता हैं। मेरे माता-पिता के भीतर उनके माता-पिता की जीवन-कथा है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं को एक लंबी जीवन-शृंखला की कड़ी के रूप में देख सकता है। यहीं श्राद्ध कृतज्ञता की परंपरा बन जाता है। अद्वैत दर्शन भी कहता है कि अस्तित्व मूलतः विभाजित नहीं है। व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, लेकिन व्यापक अस्तित्व में सब एक ही निरंतरता का हिस्सा हैं। आधुनिक विज्ञान की भाषा अलग है। विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा, कोशिका, अणु, परमाणु, आनुवंशिकी और जैविक प्रक्रियाओं की बात करता है। फिर भी दोनों के बीच एक संवाद संभव है। ब्रह्मांड में पदार्थ निरंतर रूप बदलता है। पृथ्वी के तत्व हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं। भोजन शरीर में जाता है। शरीर प्रकृति में लौटता है। जीवन की जैविक निरंतरता पीढ़ियों के जरिए आगे बढ़ती है। भारतीय चिंतन इसी निरंतरता को पंचमहाभूत, जीवन-चक्र और पूर्वज परंपरा की भाषा में देखता रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण यह नहीं कहते कि श्राद्ध या तर्पण करने से किसी का डीएनए सीधे बदल जाता है। इसी तरह तर्पण को आनुवंशिक रोगों के उपचार का वैज्ञानिक तरीका भी नहीं माना जा सकता। लेकिन मनुष्य केवल डीएनए नहीं। उसके भीतर

स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं, रिश्ते, संस्कार हैं और जीवन को देखने की धारणाएं हैं। यदि किसी पारिवारिक दुख को समझने, स्वीकारने व उसके साथ स्वस्थ संबंध बनाने से व्यक्ति के तनाव और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है, तो उसका प्रभाव मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। इस तरह ‘हीलिंग’ का अर्थ डीएनए बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक व व्यावहारिक धारणाएं पहचानना हो सकता है। आजकल बच्चों को अपने दादा-दादी और परदादा-परदादी की कहानियां तक पता नहीं होतीं। ऐसे समय में श्राद्ध हमें पूछने का अवसर देता है-हम कहाँ से आए हैं और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? शायद तर्पण केवल अतीत को जल देने का नाम नहीं। खुद में कृतज्ञता जगाने का अवसर भी है। यह भी कि हम एक लंबी जीवन-यात्रा की कड़ी हैं। शायद यही श्राद्ध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है-पूर्वजों को मुक्त करने से पहले अपने भीतर जमा भावनाओं को मुक्त करना। जब श्रद्धा भय से निकलकर कृतज्ञता बनती है, तब श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं रहता। वह आत्मचिंतन बन जाता है, परिवार की स्मृति बन जाता है। ...और आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण बन जाता है।

विचार

देश में हुए व्यापक बदलावों को देखने-समझने का अवसर

मनोहर लाल खट्टर

7 अक्टूबर 2026 को श्री नरेंद्र मोदी ने एक सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह सार्वजनिक जीवन की ऐसी यात्रा है, जिसकी शुरुआत साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से हुई और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ी। यह वह दौर है, जिसमें भारत ने आर्थिक, तकनीकी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखा है। एक-चौथाई सदी का यह पड़ाव राजनीतिक उपलब्धियों से आगे बढ़कर देश में हुए व्यापक बदलाव को देखने-समझने का अवसर प्रदान करता है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, सामाजिक कल्याण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। समर्थक इस अवधि को तेज गति से हुए राष्ट्र-निर्माण का दौर बताते हैं, जबकि आलोचकों और स्वतंत्र विश्लेषकों ने क्रियान्वयन, संस्थागत प्रक्रियाओं और आर्थिक लाभों के वितरण को लेकर प्रश्न उठाए हैं। इसलिए इस पूरे दौर को समझने के लिए मापनीय बदलावों के साथ-साथ उनसे जुड़े विमर्शों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस अवधि की प्रमुख विशेषताओं में से एक ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसररचना’ का विस्तार रहा है। 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता की, जिसमें पहचान, बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवाएं बड़े पैमाने पर संचालित हो सकें। मार्च 2026 तक भारत में 144 करोड़ से अधिक आधार पहचानें, 57.71 करोड़ जन धन खाते व तेजी से विस्तारित होता डिजिटल सेवाओं का नेटवर्क मौजूद था। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) इस परिवर्तन के सबसे स्पष्ट प्रतीकों में से एक है। वित्त वर्ष 2016-17 में लगभग 2 करोड़ वार्षिक लेन-देन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन-देन 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। यूपीआई का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी वालों, उपभोक्ताओं और उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अधिक आसानी से भाग लेने में मदद की। वहीं डिजिटल, उमंग, कॉमन सर्विस सेंटर और भारतनेट जैसे प्लेटफॉर्मों ने सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच का विस्तार किया है।

‘बुनियादी ढांचा’ भी इस अवधि का प्रमुख स्तंभ रहा है। पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जलमार्गों, आवास, ऊर्जा और शहरी परिवहन में निवेश को तेज किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक भारतीय रेल नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका था, जबकि देश का मेट्रो नेटवर्क 1,155 किलोमीटर से अधिक हो गया था। वहीं विनिर्माण और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया है। ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और व्यापक ‘आत्मनिर्भर भारत’ ढांचे के जरिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा तक कई रणनीतिक क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने का प्रयास किया गया। इस अवधि में जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए आधार तैयार किया, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा सके। आवास, स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन, पेयजल, स्वास्थ्य बीमा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर बुनियादी घरेलू जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव में सरकार ने दावा किया कि इस दौरान 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहयोग से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक संचालित किया जिसके जरिए 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी गईं, जबकि ईसंजीवनी जैसी डिजिटल सेहत पहलों ने टेलीमैडिसिन की पहुंच बढ़ाई। मोदी काल में भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ की आवाज, एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और विनिर्माण अर्थव्यवस्था तथा जलवायु कार्रवाई से लेकर डिजिटल सार्वजनिक अवसररचना तक विभिन्न वैश्विक पहलों में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। साल 2023 में जी20 की सफल अध्यक्षता ने भारत को विकास संबंधी चिंताओं, डिजिटल समावेशन और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हितों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर अधिक प्रमुखता से रखने का मंच प्रदान किया। डिजिटल भुगतान और आधार से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और एआई तक, नीतिगत जोर तेजी से स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण की ओर बढ़ा है। हालांकि, इस दौर में भारत की यात्रा रोजगार, असमानता, कृषि संकट, केंद्र-राज्य संबंधों, सामाजिक समरसता व विमर्श की गुणवत्ता जैसे अहम प्रश्नों से भी जुड़ी रही है।

एक नजर

अनुशासनहीनता के आरोप में पुलिस पदाधिकारी निलंबित

परिचमचम्पारण(बगहा)। पुलिस अधीक्षक, बगहा ने ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता और मनमाने आचरण के मामलों में दो पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। भितहा थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (सअनि) राजकुमार राम को ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहने, अनुशासनहीन व्यवहार करने, थाना की गोपनीयता भंग करने तथा पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में राजकुमार राम को सामान्य जीवनयापन भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, बगहा निर्धारित किया गया है। उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है।वहीं, गोवर्धना थाना से संबंधित एक मामले में शिकायत एवं उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा के बाद पुलिस अधीक्षक ने गोवर्धना थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक जितेन्द्र कुमार राय के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मामला गोवर्धना थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी एक आवेदक द्वारा लकड़ी काटने को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित था। आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने बिना किसी वरीय पदाधिकारी की अनुमति अथवा समुचित जांच के विवादित लकड़ी को 10 सितंबर 2026 को एक पक्ष के प्रभाव में आकर उसे सौंप दिया। मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मनमानेपन एवं अनुशासनहीनता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने जितेन्द्र कुमार राय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर पुलिस केंद्र, बगहा में योगदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा मनमाने आचरण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जिला में 45 मिमी बारिश, अगले तीन दिनों में हल्के बादल के बीच मौसम शुष्क रहने का अनुमान

बक्सर,एजेंसी। जिले में बुधवार को 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र, बक्सर के पूर्वानुमान के अनुसार 8 से 10 अक्टूबर तक आसमान में हल्के बादल छाप रह सकते हैं, जबकि मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, एक–दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है।

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80–90 प्रतिशत और दोपहर में 60–80 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में करीब 8–10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरवा हवा चल सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम को देखते हुए किसानों को फसलों की विशेष निगरानी करने की सलाह दी है। दुग्धस्थथा में पहुंच चुकी धान की फसल में गंधी कीट की निगरानी करने को कहा गया है। प्रकोप दिखाई देने पर फालीडोल 10 प्रतिशत धूल का 10–15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह 8 बजे से पहले अथवा शाम 5 बजे के बाद बालियों पर छिड़काव करने की सलाह दी गई है। वहीं, भिंडी की फसल में फल एवं प्ररोह बेशक कीट की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। प्रभावित कलियों को तोड़कर मिट्टी में दबाने की सलाह दी गई है। अधिक प्रकोप होने पर बिबनालफॉस 25 ईसी दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर, आसमान साफ रहने पर छिड़काव करने की सलाह दी गई है।

‘क्या फर्क पड़ता है’ नुक्कड़ नाटक में विद्यार्थियों ने दिखाई रंगमंचीय प्रतिभा

दरभंगा,एजेंसी। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के नाट्य विषय के तृतीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के शिक्षाशास्त्र विभाग परिसर में समसामयिक नुक्कड़ नाटक ‘क्या फर्क पड़ता है’ की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। व्यावहारिक परीक्षा के तहत आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अभिनय, संवाद- अदायगी, सामूहिक समन्वय एवं रंगमंचीय कौशल का प्रदर्शन किया। नाटक का आयोजन संगीत एवं नाट्य विभाग की संकायाध्यक्ष सह विभागाध्यक्ष प्रो. लावण्य कीर्ति सिंह ‘काव्या’ के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में हुआ। परीक्षा का समन्वय शिक्षाशास्त्र विभाग के प्रदर्शन कला के प्राध्यापक डॉ. अक्षय कुमार ने किया। शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार मिलन ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा में संगीत एवं नाट्य का समावेश शिक्षण– अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रुचिकर एवं संवेदनशील बनाता है। ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक विधाओं के बीच ज्ञान एवं अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। संगीत एवं नाट्य विभाग ने आयोजन में सहयोग के लिए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रो. हरे कृष्ण सिंह के प्रति आभार जताया। मौके पर डॉ. सुनील कुमार ठाकुर, विभागीय कर्मचारी कुंदन कुमार सहित शिक्षाशास्त्र विभाग के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं करीब 100 विद्यार्थी मौजूद थे। दर्शकों ने प्रस्तुति की सराहना करते हुए प्रतिभागी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम से दोनों विभागों के बीच शैक्षणिक एवं कलात्मक समन्वय को भी मजबूती मिली

दुर्गापूजा–दशहरा को लेकर प्रशासन सख्त, बिना अनुमति नहीं निकलेगा जुलूस

बक्सर,एजेंसी। दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 11 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले पर्व को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विधि–व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने पूजा पंडालों, प्रतिमा स्थापना और जुलूस के लिए शत–प्रतिशत अनुज्ञप्ति अनिवार्य कर दी है। बिना अनुमति किसी भी आयोजन की इजाजत नहीं होगी। जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी, उत्तेजक गतिविधियों और प्रतिस्पर्धित हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी। आयोजन से 10 से 25 व्यक्तियों का अंडरटैकिंग लिया जाएगा तथा जुलूस की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। पंडालों और जुलूसों में आपत्तिजनक झांकी, दृश्य, व्यंग्यचित्र, डीजे और अश्लील गानों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। सभी डीजे एवं लाउडस्पीकर संचालकों को संबंधित अनुमंडल कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी। धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन सुराज के शिक्षक व स्नातक प्रत्याशियों को विजयी बनाएं : प्रशांत किशोर

नवादा,एजेंसी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना और व्यवस्था में बदलाव के लिए जाति व धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की जरूरत है। उन्होंने स्नातक एवं शिक्षक मतदाताओं से जन सुराज के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह तथा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति को विजयी बनाने की अपील की। प्रशांत किशोर बुधवार को नवादा में आयोजित स्नातकों एवं शिक्षकों की महती सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को हराकर जन सुराज के प्रत्याशियों को जीत दिलाना जरूरी है। उनके अनुसार जन सुराज का नेतृत्व जनहित को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को जाति और धर्म के आधार पर राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर मतदान करना चाहिए।

प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव का जिन्न करते हुए कहा कि मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर मतदान किया था, लेकिन बाद में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने इसे जनभावनाओं के अनादर के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग अक्सर कहते हैं कि प्रशांत किशोर अच्छा बोलते हैं, लेकिन चुनाव में समर्थन नहीं देते। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि यदि बिहार का नवनिर्माण करना है तो व्यवस्था में बदलाव के लिए जन सुराज के प्रत्याशियों को समर्थन देना होगा। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं का जिन्न करते हुए कहा कि जन

डीडीसी ने कदमहा पंचायत में विकास योजनाओं का लिया जायजा

सुपौल,एजेंसी। उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार ने बुधवार को मरौना प्रखंड की कदमहा पंचायत में विभिन्न विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत में चल रहे विकास कार्यों और कायाकल्प अभियान के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त ने पंचायत में कराए जा रहे ईट सोलिंग, पीसीसी सड़क सहित अन्य विकास कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी ली और स्थानीय लोगों से भी योजनाओं के संबंध में पृछताछ की। स्थानीय लोगों से कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। कायाकल्प अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय गिरमोहन टोला में निर्माणाधीन चारदीवारी का भी उप विकास आयुक्त ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित कर्मियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कराने का निर्देश दिया।

रुफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक अतिरिक्त सौर बिजली पर भी मिलेगा उपभोक्ताओं को लाभ

पटना। नेट मीटरिंग व्यवस्था में उपभोक्ता अपने घर पर लगे सोलर प्लांट से बिजली बनाता है। पहले इस बिजली का उपयोग उसके घर की जरूरत के लिए होता है। इसके बाद यदि कुछ बिजली बच जाती है, तो वह बिजली ग्रिड में चली जाती है। इस अतिरिक्त बिजली का समायोजन हर महीने के बिजली बिल में किया जाता है। यदि किसी महीने सोलर से बनी बिजली खरात से अधिक होती है, तो बची हुई बिजली का लाभ अगले महीने में ले जाया जाता है।

इस तरह उपभोक्ता की अतिरिक्त बिजली अगले महीनों की खपत के साथ समायोजित होती रहती है। लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में जो अतिरिक्त बिजली बच जाती है, उसका क्रेडिट वर्तमान व्यवस्था में समाप्त हो जाता है। उपभोक्ताओं को उनकी अतिरिक्त सौर बिजली का लाभ मिल सके और बिहार में सोलर को और बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ऊर्जा विभाग ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीआईआरसी) से इस संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष के अंत में उपभोक्ता के खाते में बची अतिरिक्त बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाएगी। इससे उपभोक्ता को अपनी अतिरिक्त उत्पादित बिजली का भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इससे लोगों को अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं ने पहले से सोलर प्लांट लगा रखा है, उन्हें भी



सुराज की सरकार बनने पर शिक्षकों को सम्मान के साथ सातवां वेतनमान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वित्त रहित एवं वित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही बचे हुए शिक्षकों के समायोजन की दिशा में भी काम किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने स्नातक मतदाताओं से जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जिस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज का प्रत्याशी विजयी होगा, वहां 10 हजार पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार देने के वादे को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके युवाओं की वापसी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने

दियारा में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुंगेर के कारीगरों समेत 4 गिरफ्तार

भागलपुर,एजेंसी। अवैध हथियारों के सिंडिकेट के खिलाफ नवगछिया पुलिस और बिहार एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भवानीपुर थाना क्षेत्र के बांधा बहियार स्थित दियारा इलाके में चल रही एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से हथियार बना रहे चार शांति कारीगरों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अंधेरे और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भाग निकला। नवगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पूरी कार्रवाई का ब्योरा साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को नवगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर को पुलिस को एक पुख्ता इनपुट मिला था। सूचना थी कि वीरबन्ना का रहने वाला मृत्यंजय यादव अपने साढ़ू मुकेश यादव के साथ मिलकर बाहर से शोरेवर कारीगरों को बुला रहा है और दियारा के सुनसान इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनावा रहा है। इस सूचना के बाद नवगछिया पुलिस और एसटीएफ की एक संयुक्त विशेष टीम बनाई गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बांधा बहियार दियारा में घेराबंदी कर अचानक धावा बोल दिया। पुलिस की इस अचानक हुई छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जिसमें 2 देशी पिस्टल, 6 जंदा कारतूस, मैगजीन 5 पीस और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और गन बनाने के कटर, रेती सहित कई आधुनिक उपकरण



शामिल है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से तीन मुख्य रूप से मुंगेर के रहने वाले हैं, जो हथियार बनाने में माहिर माने जाते हैं। गिरफ्तार आरोपितों में मोहम्मद तौसिक उर्फ साधो (बरदह, मुंगेर), मोहम्मद अरमान उर्फ मेहरूद्दीन (मिर्जापुर बधो, मुंगेर), मुकेश यादव (मुफस्सिल, मुंगेर) और मनीष कुमार यादव (भवानीपुर, भागलपुर) शामिल है। वहीं पुलिस

को देखकर मुख्य सरगना मृत्यंजय यादव (निवासी वीरबन्ना) मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसपी ने कहा कि अपराध और अवैध हथियारों के इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा और दियारा क्षेत्र में सच आँपरेशन आगे भी जारी रहेगा।

दुर्गापूजा में डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, पंडालों में सीसीटीवी अनिवार्य

दरभंगा,एजेंसी। दुर्गापूजा को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय के डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में विधि–व्यवस्था, यातायात, साफ–सफाई, पेयजल, प्रकाश, प्रकाश, अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य, मूर्ति विसर्जन एवं पार्किंग सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पूजा स्थलों एवं शहर में साफ–सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पहुंच पथ और नागरिक सुविधाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बिहार विधान सभालेन डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपद्रव या विधि–व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ सदर कुमार गौरव ने पूजा समितियों से अथवा अन्धर्थी से संबंधित पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी।

डीएम ने सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने और निगरानी संबंधी साइनेज प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। पूजा समितियों के वॉलंटियर्स की सूची संबंधित थानों को उपलब्ध कराने को कहा गया। अग्निशमन विभाग को पंडालों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा विद्युत विभाग को तार, कनेक्शन सहित विद्युत व्यवस्था की जांच करने का निर्देश दिया गया। मूर्ति विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग एवं समय का पालन कराने के साथ विसर्जन स्थलों पर बैरिकेडिंग, रोशनी, सुरक्षा

दुर्गा पूजा को लेकर कटिहार प्रशासन अलर्ट: डीएम व एसपी ने दिए चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश

कटिहार। आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कटिहार जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। बिहार के मुख्य सचिव से मिले निर्देशों के आलोक में बुधवार को जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पूजा से जुड़ी तमाम प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्थाएं समय रहते हर हाल में पूरी कर ली जाएं।

समीक्षा बैठक के दौरान डीएम और एसपी ने निर्देश दिया कि मेले और पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वच्छता, निर्बाध पेयजल आपूर्ति, 24 घंटे विद्युत व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस तथा अग्निशमन जैसी अनिवार्य सेवाओं को पुख्ता तैनाती रहे। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्यबल को सक्रिय रखने को कहा गया है, ताकि आमजन और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। विधि–व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी ने



अनुमंडल व थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पूजा समितियों के साथ निरंतर संवाद व समन्वय स्थापित रखा जाए। इसके साथ ही संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, भेड़ नियंत्रण और सुगम यातायात प्रबंधन की लगातार मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया। जिला प्रशासन ने कटिहार की जनता से अपील की है कि वे दुर्गा पूजा का पावन पर्व आपसी भाईचारे, सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और एक सुरक्षित व शांतिपूर्ण वातावरण के निर्माण में सभी का सहयोग अपेक्षित है। आमजन से प्रशासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

एक नजर

मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने आखिरी मैच में पेनल्टी पर किया गोल, दो गोल में दिया सहयोग



व्यूनस आयरस,एजेंसी। लियोनेल मेसी ने मंगलवार को व्यूनस आयरस के एस्टाडियो मोनुमेंटल स्टेडियम में बेनिन के खिलाफ अर्जेंटीना के लिए अपने अंतिम मैच को गोल और दो सहायताओं के साथ यादगार बना दिया। मेसी ने पेनल्टी पर गोल करते हुए अपनी विदाई को शानदार अंदाज में पूरा किया। 39 वर्षीय मेसी ने अर्जेंटीना के फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन के हाथों 0–1 की करीबी हार के कुछ दिन बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद बेनिन के खिलाफ मुकाबला अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ उनका विदाई मैच बना।

मैच में मेसी ने दूसरे हाफ में दो गोल में सहयोग करते हुए अर्जेंटीना को 2–0 की बढ़त दिलाई। उन्होंने 48वें मिनट में अपने लंबे समय से टीम के साथी निकोलस ओटामेंडी को गोल करने में मदद की। ओटामेंडी का भी यह अर्जेंटीना की जर्सी में आखिरी मुकाबला था। इसके बाद मेसी ने 61वें मिनट में निको पाज के गोल में सहयोग किया। पाज को अर्जेंटीना के लिए दाएं विंग में मेसी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है। इसके दस मिनट बाद मेसी को खुद गोल करने का मौका मिला। अर्जेंटीना को पेनल्टी मिलने पर मेसी ने जिम्मेदारी संभाली और गेंद को गोलपोस्ट के ऊपरी दाएं कोने में भेजकर टीम का तीसरा गोल किया। इस तरह मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने अंतिम मुकाबले में एक गोल और दो गोल में सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय करियर का यादगार समापन किया।

मेसी ने अर्जेंटीना को कहा अलविदा, बोले- मुझे इसकी कमी खलेगी



व्यूनस आयरस,एजेंसी। लियोनेल मेसी ने मंगलवार को व्यूनस आयरस में बेनिन के खिलाफ 3–0 की जीत के साथ अर्जेंटीना के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन किया। दो गोल में सहयोग और एक पेनल्टी पर गोल करने के बाद मेसी ने खचाखच भरे एस्टाडियो मोनुमेंटल में भावुक भाषण दिया और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम को अलविदा कहा। मेसी ने कहा कि वह अर्जेंटीना के लिए खेलना याद करेंगे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अपने दिवंगत पिता जॉर्ज को याद करते हुए की, जिनका लंबी बीमारी के बाद अगस्त में निधन हो गया था। मेसी ने कहा, ‘आज रात मैं जिस पहले व्यक्ति के बारे में सोचता हूं, वह मेरे पिता हैं। मैं आप सभी का सिर्फ धन्यवाद कर सकता हूं।20 से अधिक वर्षों तक इस जर्सी की रक्षा करना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात रही है। हमने कभी लड़ना बंद नहीं किया, कभी अपना सब कुछ देना बंद नहीं किया।

उन्होंने कहा, ‘मेरी इच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी खेल सकूँ, क्योंकि अर्जेंटीना के लिए खेलना सबसे खूबसूरत चीज है। मेसी ने कहा, ‘बेशक, मैं शायद बहुत सी ऐसी बातें भूल रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। यह मेरे लिए एक मुश्किल पल है। मुझे इसकी कमी खलेगी। 39 वर्षीय मेसी ने यह भी कहा कि वह अर्जेंटीना के लिए उनके बाद खेलने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी अन्य टीम से ज्यादा मजबूत होते हैं। और हम किसी भी चीज से पार पा सकते हैं। मेसी ने अपने भावुक भाषण का समापन करते हुए कहा, ‘मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे आपकी कमी खलेगी। और मैं अर्जेंटीना का होने पर बेहद आभारी और गौरवान्वित हूँ। आप सभी के साथ अपना सपना पूरा करने पर मुझे गर्व है।’

गंभीर ने अजित अगरकर की सराहना की, कहा– इतिहास आपके प्रति अधिक उदार रहेगा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बुधवार को चयन समिति के निवर्तमान अध्यक्ष अजित अगरकर की जमकर सराहना की। गंभीर ने कहा कि ‘टीम पहले’ की सोच और दृढ़ विश्वास ने अगरकर के कार्यकाल में भारत को तीन आईसीसी खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई और ‘इतिहास आपके प्रति अधिक उदार रहेगा। अगरकर का चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इससे पहले कई सप्ताह तक अगरकर को कार्यकाल विस्तार दिए जाने को लेकर अटकलें चलती रही थीं। गंभीर ने सोशल मीडिया पर अगरकर के लिए भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, ‘प्रिय अजित भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात रही। वे तीन आईसीसी ट्राँफियां आपके विश्वास की गवाही देती हैं: हमेशा टीम पहले और टीम से आगे। मुझे कहना होगा कि इतिहास आपके प्रति अधिक उदार रहेगा। हर चीज के लिए धन्यवाद। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं। अगरकर के कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 का टी20 विश्व कप तथा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का दौर भी आया, जिसमें बल्लेबाजी के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्रमशः टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अगरकर को कई मौकों पर कड़े फैसले लेने वाले चयनकर्ता के रूप में देखा गया। वह इस सवाल पर भी स्पष्ट रुख अपनाने से बचते रहे कि कोहली और रोहित 2027 के एकदिवसीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं में शामिल हैं या नहीं।

आईओए ने 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए ‘साथ बढ़ते भारत’ की परिकल्पना रखी

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की परिकल्पना पेश करते हुए इसे दो प्रभावशाली शब्दों- ‘साथ बढ़ते भारत’ में व्यक्त किया है। आईओए ने कहा कि भारत में 2036 खेलों का आयोजन देश में खेलों के माध्यम से बदलाव की गति तेज करने के साथ-साथ ओलंपिक आंदोलन के लिए सार्वभौमिक विस्तार का नया अध्याय खेल सकता है। आईओए ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इस सप्ताह 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के भावी मेजबान के चयन की प्रक्रिया में शामिल शहरों और देशों की घोषणा का स्वागत किया।

गुजरात के अहमदाबाद केंद्रित भारत की ओलंपिक और पैरालंपिक मेजबानी की महत्वाकांक्षा पिछले 18 महीनों में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ करीबी और रचनात्मक संवाद के जरिए विकसित की गई है। ‘साथ बढ़ते भारत’ की परिकल्पना इस विश्वास पर आधारित है कि 2036 ऐसा अवसर हो सकता है, जब खेलों के माध्यम से भारत का बदलाव और ओलॉंपिक आंदोलन का सार्वभौमिक भविष्य एक साथ आगे बढ़े। भारत के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी राष्ट्रीय जीवन के केंद्र में खेलों को स्थापित करने का पीढ़ीगत अवसर होगी। इस परियोजना को व्यापक खेल परिवर्तन के उत्तरक के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे लाखों युवा केवल खेल देखने के बजाय उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित हों। इसके साथ स्वस्थ और सक्रिय समुदायों को बढ़ावा देने तथा शिक्षा और पर्योग के अवसरों में खेलों की भूमिका बढ़ाने पर भी जोर होगा। भारत में खेलों के आयोजन का

श्रेयस अय्यर टी20 रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ सातवें स्थान पर, वनडे में शुभमन गिल शीर्ष पर कायम

नई दिल्ली। भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर बुधवार को जारी ताजा आईसीसी रैंकिंग में टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी सूची में करियर के सर्वश्रेष्ठ सातवें स्थान पर पहुंच गए, जबकि एकदिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने 50 औवर के प्रारूप में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

अय्यर ने मंगलवार को लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के पहले मुकाबले में 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत विश्व चैंपियन भारत ने मुकाबला आठ विकेट से जीता। आईसीसी के अनुसार, अय्यर इस पारी के बाद 18 स्थान की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गए और टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के तीसरे सबसे ऊंचे रैंकिंग वाले बल्लेबाज बन गए। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा शीर्ष दो स्थान पर कायम हैं, जबकि तिलक वर्मा 10वें स्थान पर हैं। इस तरह भारत के चार बल्लेबाज शीर्ष 10 में शामिल हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी आठ स्थान ऊपर चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरेफन रदरफोर्ड ने 56

रनों की तेजतर्रार पारी के बाद 10 स्थान की छलांग लगाकर 37वां स्थान हासिल किया। वहीं, एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के हसन नवाज 62 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में एशियाई खेलों के सेमीफाइनल और फाइनल में क्रमशः 29 रन पर कोई विकेट नहीं और 29 रन पर एक विकेट लेने वाले अबरार अहमद अपना शीर्ष स्थान बरकरार नहीं रख सके। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान फिर से टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। यह आठवीं बार है जब राशिद शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं।वह किसी भी अन्य गेंदबाज की तुलना में दोगुने से अधिक समय तक नंबर एक रह चुके हैं। भारत के बाएं हाथ के स्पिनर अश्वर पटेल ने पिछले सप्ताह तीन मैचों में दो-दो विकेट लिए। इसके बाद उन्होंने 16 स्थान की छलांग लगाकर सातवां स्थान हासिल किया। शुभमन गिल ने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच में नाबाद 223 रनों की पारी के बाद वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान और मजबूत किया है।

मुंबई,एजेंसी। भारत में क्रिकेट देखने के तौर-तरीकों में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। जियोस्टार ने बुधवार को ‘बिगॉन्ड बाउंड्रीज’ पहल शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विज्ञापनदाताओं को क्षेत्रीय भाषा में क्रिकेट देखने वाले बढ़ते और सक्रिय दर्शकों से जोड़ना है। इस पहल में लाइव क्रिकेट फीड के साथ सैथ से पहले और बाद के कार्यक्रमों के लिए साझेदारी के अवसर शामिल हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के दौरान जियोहॉटस्टार पर कन्नड़ फीड की पहुंच में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तेलुगु और तमिल फीड की पहुंच में क्रमशः 23 और 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। डिजिटल पर देखने के कुल समय में तेलुगु भाषा की हिस्सेदारी में तीनों बाजारों के बीच सबसे अधिक 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद कन्नड़ और तमिल का स्थान रहा। यह वृद्धि दर्शाती है कि क्रिकेट की खपत अब हिंदी और अंग्रेजी तक सीमित नहीं है और दर्शक तेजी से ऐसे फीड से जुड़ रहे हैं, जहां लाइव खेल के साथ उनकी भाषा और सांस्कृतिक जुड़ाव भी मौजूद है। प्रत्येक क्षेत्रीय फीड ने अपने-अपने बाजार की घरेलू प्रेंचाइज और प्रशंसकों को ध्यान में रखते हुए अलग कार्यक्रम पहचान भी विकसित की। टाटा आईपीएल 2026 में तेलुगु फीड पर ‘क्रिकेट विद चाय’ और ‘ऑरिज ओ रंगु’, कन्नड़ फीड पर ‘केम्पु सैन्ना’ और ‘इनसाइड आरसीबी’ जैसे विशेष कार्यक्रम



उद्देश्य केवल वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी करना नहीं है बल्कि रोजमर्रा के जीवन में खेलों को और गहराई से स्थापित करना तथा ऐसी विरासत तैयार करना है, जो भारत की ऊर्जा, युवा शक्ति और समाज को बदलने में खेलों की क्षमता में उसके विश्वास को दर्शाए। ओलंपिक आंदोलन के लिए भारत में 2036 खेलों का आयोजन सार्वभौमिकता के एक नए दौर में प्रवेश का अवसर होगा। इससे ओलंपिक और पैरालंपिक आंदोलन दुनिया की सबसे युवा, गतिशील और डिजिटल रूप से जुड़ी आबादी में से एक के साथ और मजबूत तरीके से जुड़ सकेगा। इससे एक अरब से अधिक लोगों तक ओलंपिक खेलों की पहुंच बढ़ाने के साथ नए खिलाड़ियों, दर्शकों और साझेदारों को ओलंपिक परिवार से जोड़ने की क्षमता पैदा होगी। आईओए की अध्यक्ष पी. टी. उषा ने कहा, ‘हम 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए भारत की परिकल्पना और आकांक्षाओं को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मान्यता मिलने से बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं और भविष्य के खेलों के संभावित मेजबानों के एक असाधारण समूह का

मुख्य कोच की नजर लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर, भारतीय मुक्केबाजों से शुरुआती दौर में अधिक कोटा हासिल करने का लक्ष्य

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच सैंटियागो नीवा ने 2026 एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए अधिक से अधिक कोटा जल्द हासिल करने को अपना अगला लक्ष्य बनाया है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने तीन पदक जीते, जिसमें दो स्वर्ण शामिल हैं। ओलंपिक के लिए पहला प्रमुख क्वालीफिकेशन मार्ग 2027 में कजाकिस्तान में होने वाली विश्व चैंपियनशिप से शुरू होगा। नीवा ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) मीडिया से कहा, ‘पहला क्वालीफायर कजाकिस्तान में होगा, जो विश्व चैंपियनशिप है, जहां आदर्श रूप से हम अधिक से अधिक कोटा हासिल करना चाहेंगे। इसके बाद एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर होगा और 2028 में दो और ओलंपिक क्वालीफायर होंगे।’

ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने छह पदक जीते थे, जिनमें पांच स्वर्ण शामिल थे। इसके बाद आइची-नागोया एशियाई खेलों में तीन पदकों के प्रदर्शन ने भारतीय महिला मुक्केबाजों के लिए शानदार वर्ष पूरा किया। नीवा का लक्ष्य है कि उनकी अधिक से अधिक खिलाड़ी शुरुआती चरण में ही लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लें, जिससे टीम को ओलंपिक की विशेष तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नीवा ने कहा, ‘अगर हम आदर्श रूप से अगले साल शुरुआत में ही क्वालीफाई कर लेते हैं तो हमें अच्छी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह एक कठिन क्वालीफिकेशन मार्ग होगा और उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक मुक्केबाजों को क्वालीफाई

क्षेत्रीय भाषाओं में क्रिकेट की बड़ी लोकप्रियता, जियोहॉटस्टार पर कन्नड़ फीड की पहुंच 30 प्रतिशत बढ़ी



शामिल रहे। तमिल फीड पर मैच वाले दिन ‘इनी सिंगापथई’ की थीम के साथ कार्यक्रम पेश किए गए। तीनों बाजारों में उभरती युवा प्रतिभाओं पर भी विशेष खंड प्रसारित किए गए। क्षेत्रीय भाषाओं में क्वेज को 12 भाषाओं में 160 से अधिक कमेंटेटरों और विशेषज्ञों के पैनल ने मजबूती दी। इसमें पूर्व क्रिकेटरों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने अपने-अपने बाजार में कमेंट्री की। तमिल फीड के पैनल में मुरली विजय और एल. बालाजी के साथ श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल अर्नॉल्ड और आरजे बालाजी शामिल रहे। तेलुगु फीड में हनुमा विहारी और एमएसके प्रसाद, जबकि कन्नड़ फीड में विनय कुमार और वेदा कृष्णमूर्ति ने कमेंट्री की। जियोस्टार ने प्रत्येक क्षेत्रीय फीड को एक राष्ट्रीय कमेंट्री टीम के बजाय स्थानीय स्तर पर पहचाने जाने वाले चेहरों और आवाजों के साथ तैयार किया। टाटा आईपीएल 2026 में डिजिटल माध्यमों पर भी मजबूत वृद्धि देखने को मिली। कनेक्टेड टीवी की पहुंच में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डिजिटल वीडियो व्यूज 25 अरब तक पहुंचे, जो सालाना

आधार पर आठ प्रतिशत अधिक है। वहीं, डिजिटल पर क्षेत्रीय भाषाओं में देखने के कुल समय की हिस्सेदारी में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जियोस्टार ने खेल बिक्री प्रमुख अनूप गोविंदन ने कहा, ‘क्षेत्रीय भाषाओं में क्रिकेट की वृद्धि दर्शाती है कि भारत में क्रिकेट देखने का तरीका किस तरह बदल रहा है। दर्शक केवल बड़ी संख्या में नहीं देख रहे हैं बल्कि वे खेल का अनुभव उन भाषाओं और वातावरण में करना पसंद कर रहे हैं, जो उन्हें परिचित लगते हैं। बांड के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अलग-अलग बाजारों में क्रिकेट से गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर मिलता है। वास्तविक अवसर यह समझने में है कि प्रत्येक दर्शक और बाजार को क्या अलग बनाता है और उन्हीं बारीकियों के आधार पर रणनीति तैयार करना है, न कि क्षेत्रीय खपत को केवल पहुंच के पैमाने से देखना। जियोस्टार के अनुसार, अलग-अलग मंचों पर क्षेत्रीय भाषा के फीड को लगातार बड़ी संख्या में दर्शक मिल रहे हैं। इससे दर्शकों, विज्ञापनदाताओं और साझेदारों के लिए भारत के विभिन्न बाजारों में क्रिकेट से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जियोस्टार के लिए अलग-अलग भाषाओं में बढ़ती दर्शक संख्या खेल देखने के परिदृश्य में व्यापक बदलाव का संकेत है। क्षेत्रीय भाषा के फीड अब मुख्य प्रसारण के विस्तार भर नहीं रह गए हैं बल्कि क्रिकेट के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं।

प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों में होंगे भारत के ध्वजवाहक

नई दिल्ली। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल 18 अक्टूबर को जापान के नागोया में होने वाले आइची-नागोया 2026 एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। दोनों खिलाड़ी भारत के सबसे सफल पैरा खिलाड़ियों में शामिल हैं और उनकी उपलब्धियों ने देश में पैरा खेलों को नई पहचान दिलाई है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अनुसार, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में छह पदक जीते हैं, जिसमें दो स्वर्ण और चार कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने 2018 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में दो पदक जीते हैं। इनमें एक रजत और एक कांस्य पदक शामिल है। प्रमोद और भाविना ने मिलकर एशियाई पैरा खेलों में आठ पदक जीते हैं। और दोनों 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले पांचवें एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल के आगे तिरंगा लेकर चलेंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में विशेष विदाई समारोह में भारतीय दल को औपचारिक रूप से रवाना करेगी।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा

निखिल खडसे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रमोद भगत और भाविना पटेल का ध्वजवाहक चुना जाना विशेष महत्व रखता है। दोनों खिलाड़ी भारत में पैरा खेलों के विकास में अग्रणी रहे हैं और लगातार बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहे हैं। भारतीय दल के नेतृत्व में उनकी मौजूदगी भागीदारी से प्रदर्शन और प्रतिनिधित्व से वैश्विक पैरा खेलों में पहचान हासिल करने तक भारत के सफर का प्रतीक मानी जा रही है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र झाझरिया ने कहा, ‘उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल को भारतीय दल का नेतृत्व करते देखना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है।

दोनों असाधारण चैंपियन हैं, जिन्होंने भारतीय पैरा खेलों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका सफर, उपलब्धियां और

दृढ़ता उन्हें भारतीय दल के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत करने वाले हमारे खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे। भाविना पटेल ने कहा,

‘भारत की ध्वजवाहक चुना जाना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। जब आप तिरंगा लेकर चलते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपने से कहीं बड़ी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।



का सकेगे, ताकि हम ओलंपिक के लिए मजबूत टीम तैयार कर सकें। नीवा 2017 से 2021 तक भारतीय मुक्केबाजी के उच्च प्रदर्शन निदेशक रहे थे। भारतीय मुक्केबाजी व्यवस्था में उनका दूसरा कार्यकाल 2025 में राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में शुरू हुआ। अर्जेंटीना के इस कोच ने इस वर्ष टीम की सफलता का थ्रै पुरे साल चले तैयारी कार्यक्रम को दिया, जिसमें मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, घरेलू शिविर और उच्च स्तर की अभ्यास मुकाबले शामिल रहे। भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम ने इस वर्ष की बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले पटियाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में कड़ी मेहनत की। नीवा ने टीम को मिलने वाली सहयोगी व्यवस्था को अहम बताते हुए कहा कि पटियाला केंद्र में मुक्केबाजों के साथ करीब 40 लोग काम करते हैं, जिनमें लगभग 20 प्रशिक्षक और 20 अन्य सहयोगी स्टाफ शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘हमारे पास मुक्केबाजों के साथ

काम करने वाले 40 लोगों का स्टाफ है, जिनमें करीब 20 कोच और 20 अन्य सहयोगी स्टाफ हैं। खेल विज्ञान, मुक्केबाजी हॉल, मुक्केबाजी उपकरण और अन्य क्षेत्रों में सुधार हुए हैं। नीवा ने कहा कि यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी कार्यक्रमों की बराबरी करती है। उन्होंने कहा, ‘मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत ज्यादा देश नहीं हैं, जिनके पास इससे बेहतर सहयोग व्यवस्था है। भारत ने जाना जाने से पहले प्रशिक्षण के लिए डोमिनिकन गणराज्य और ईरान की टीमों को पटियाला भी बुलाया था। इसके बाद जापान में अंतिम चरण की तैयारी के दौरान भारतीय मुक्केबाजों को उच्च स्तर के अभ्यास मुकाबले मिले। नीवा ने कहा, ‘जापान में हमारी अंतिम तैयारी अच्छी रही, जहां हमें अच्छे अभ्यास मुकाबले भी मिले। हम एशियाई खेलों के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार होकर गए थे। हालांकि, हम इस प्रदर्शन पर रुक नहीं सकते। हमें लगातार आगे देखना होगा और अंत में हम सभी अगले ओलंपिक में बड़ी सफलता चाहते हैं।’

अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप शुरु, 42 देशों के 144 खिलाड़ी लैंगे हिस्सा

अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण बुधवार को अहमदाबाद में शुरू हो गया। इसमें राष्ट्रमंडल के 42 देशों के 144 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के मुकाबले 8 से 10 अक्टूबर तक वीर सावरकर खेल परिसर में खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह 7 अक्टूबर को आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित बहुविषयक प्रतियोगिता पहली बार भारत में हो रही है। अहमदाबाद में अगले तीन दिनों तक अनुभवी चैंपियन, उभरती प्रतिभाएं और भारत के शीर्ष खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। चैंपियनशिप में 72 पुरुष और 72 महिला खिलाड़ी पांच स्पर्धाओं—इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10–बॉल पूल, हीबॉल और ब्रेकबॉल—में चुनौती पेश करेंगे। चार दिवसीय आयोजन में कुल 10 पदक स्पर्धाएं होंगी। यह प्रतियोगिता भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ के शताब्दी समारोह का भी प्रमुख हिस्सा है।

भारत ने 2025 में मॉरीशस में आयोजित पहली चैंपियनशिप में पांच पदक जीते थे। घरेलू मैदान पर इस बार भारतीय चुनौती की अनुभवी महिला हीबॉल की मौजूदगी कॉमनवेल्थ चैंपियन विद्या पिल्लई, पुरुष हीबॉल के रजत पदक विजेता शिवम अरोड़ा और महिला 10–बॉल पूल की रजत पदक विजेता चित्रा मागिमैराज करेंगी। तीनों खिलाड़ी अपने पदकों की संख्या बढ़ाने के इरादे से उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों को

एक नजर

पश्चिम एशिया युद्ध में मध्यस्थता को तैयार पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत

मॉस्को/तेहरान,एजेंसी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि मॉस्को पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त कराने और तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता के प्रयासों में भूमिका निभाने को तैयार है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, पुतिन ने यह बात बुधवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान कही। महीनों से जारी संघर्ष के बीच दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। आईआरएनए के मुताबिक, पुतिन और पेजेश्कियन ने रूस-ईरान संबंधों के सकारात्मक और लगातार विस्तार की दिशा में बढ़ने पर जोर दिया तथा दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता जताई। पश्चिम एशिया संघर्ष का जिक्र करते हुए पुतिन ने कुछ देशों की ओर से तनाव कम करने और युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रूस ऐसे प्रयासों का समर्थन करता है। आईआरएनए के अनुसार, पुतिन ने पेजेश्कियन से कहा कि ईरान यह भरोसा रख सकता है कि मॉस्को भी इस दिशा में भूमिका निभाने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों में सैन्य और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। दोनों देश दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों में शामिल हैं।

यूएई ने इजराइली एयरलाइंस का लैंडिंग परमिट रद्द किया, दुबई से प्रत्यावर्तन उड़ानें रद्द

दुबई,एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा इजराइली एयरलाइंस के विमानों का लैंडिंग परमिट रद्द किए जाने के बाद दुबई से तेल अवीव के लिए संचालित की जा रही प्रत्यावर्तन उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इन विशेष उड़ानों के जरिए इजराइली नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लौटाया जा रहा था। इजराइली एयरलाइन आर्किया ने कहा कि उसने उड़ानों के संचालन की अनुमति बहाल कराने के लिए संबंधित पक्षों से संपर्क किया, लेकिन अब तक प्रयास सफल नहीं हुए। इसके चलते कंपनी को अपनी उड़ानें रद्द करने का फैसला करना पड़ा। एयरलाइन के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। आर्किया ने यह भी कहा कि जो यात्री अपने स्तर पर ऐसे किसी गंतव्य तक पहुंचते हैं, जहां से कंपनी इजराइल के लिए उड़ान संचालित करती है, उन्हें इजराइल के टिकट की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस बीच एल अल और इस्रायर ने भी दुबई से तेल अवीव के लिए कल तक प्रस्तावित अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजराइल को उम्मीद थी कि उसके विमानन कंपनियों द्वारा चलाया जा रहा नागरिकों की स्वदेश वापसी का विशेष अभियान कल तक पूरा हो जाएगा। पिछले सप्ताह दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक उड़ान पर हुए कथित आतंकवादी हमले के प्रयास के बाद इजराइली एयरलाइंस ने दुबई से विशेष प्रत्यावर्तन उड़ानें शुरू की थीं। इन उड़ानों की पहली खेप शुक्रवार देर रात बेन गुरियन हवाईअड्डे पर पहुंची थी। इजराइल के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, अब तक 7,415 से अधिक यात्री विशेष इजराइली उड़ानों के जरिए दुबई से तथा एतिहाद एयरवेज की वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से अबू धाबी से इजराइल लौट चुके हैं।

ममदानी ने 7 अक्टूबर की बरसी पर इजराइल पर लगाया ‘नरसंहार’ और ‘रंगभेद’ का आरोप



न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के मेयर जोह्रान ममदानी ने 07 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले की तीसरी बरसी पर जारी बयान में हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए हमास की निंदा की। हालांकि, उनके बयान का बड़ा हिस्सा गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना पर केंद्रित रहा। ममदानी ने इजराइल पर गाजा में ‘जारी नरसंहार’ और ‘रंगभेद’ का आरोप लगाया। ममदानी ने कहा कि 07 अक्टूबर का दिन न्यूयॉर्क के अनेक लोगों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि उस दिन हमास ने 1,100 से अधिक इजराइलियों की हत्या की और 251 लोगों को बंधक बनाया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों और उनके मित्रों के दुख में वो शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने गाजा की स्थिति का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वहां इजराइली सरकार की कार्रवाई में 74,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 21,000 से अधिक बच्चे शामिल रहे। ममदानी ने यह भी दावा किया कि कथित युद्धविराम के बाद भी 1,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ममदानी ने इजराइली हमलों में अस्पतालों के बाहर मौजूद एंबुलेंस, आवासीय इमारतों और पत्रकारों को निशाना बनाए जाने तथा मानवीय सहायता रोके जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा इन कार्रवाइयों के वित्तपोषण में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल बाद ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसमें कब्जा और रंगभेद जारी रहे तथा युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही न हो। उन्होंने अमेरिकी सरकार पर हथियारों की आपूर्ति के जरिए इजराइल के साथ कथित तौर पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया।

हेनरी बी. कागन और केंसो सोई को रसायन विज्ञान का संयुक्त नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम,एजेंसी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी. कागन और जापान के केंसो सोई को वर्ष 2026 के लिए संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नोबेल समिति ने बुधवार को स्टॉकहोम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। नोबेल समिति के मुताबिक दोनों वैज्ञानिकों को असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रैखिक प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाएगा। उनको दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष नोबेल पुरस्कार की राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना (लगभग 11.51 करोड़ रुपये) है। यह राशि दोनों विजेताओं के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति-पत्र और पदक भी प्रदान किया जाएगा।

कागन और सोई के शोध ने रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने में मदद की है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जा, जिनमें एक-दूसरे की दर्पण छवियों वाले दो अलग-अलग अणु बन सकते हैं। इन अणुओं को एनैन्टियोमर कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक कई अणु केवल इन दोनों दर्पण-रूपों में से किसी एक रूप में पाए जाते हैं। इस विशेषता को समजातीय चिरैलिटी (होमोचिरैलिटी) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों में सामान्यतः एक ही चिरल रूप का उपयोग होता है। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि प्रकृति में यह एकतरफा रासायनिक व्यवस्था कैसे विकसित

पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर सहित उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी



काठमांडू। नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित उनके करीबी बताए जाने वाले लोगों के घरों पर बुधवार को संपत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ने छापेमारी की। विभाग की टीम ने राणा के करीबी कुछ लोगों के घर पहुंचकर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए तलाशी ली। राणा से जुड़े आर्थिक लेनदेन और विभिन्न लोगों के साथ उनके संपर्क को लेकर जांच चल रही है। विभाग ने दीपक तिम्ल्सिना, नवराज थपलिया और प्रभु शमशेर राणा के घरों पर भी छापेमारी की। प्रभु शमशेर राणा, चोलेन्द्र शमशेर राणा के भाई हैं। वहीं, बर्खास्त किए गए उच्च अदालत के तत्कालीन न्यायाधीश नवराज थपलिया को भी राणा का करीबी बताया जाता है। इससे पहले राणा को काठमांडू

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय ने बिना गिरफ्तारी वारंट के हिरासत में लेकर पृछताछ की थी। पुलिस के अनुसार, उनके घर पर असामान्य गतिविधियों और सुविदाित लोगों के साथ संपर्क की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। विभाग के अनुसार, जबरा के संपर्क में रहे इनाम सापकोटा और संपत्ति शुद्धीकरण मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान हिरासत में रहे गए व्यवसायी दीपक भट्ट के बीच संबंधों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान सामने आया है कि राणा, इनाम सापकोटा के माध्यम से दीपक भट्ट समेत अन्य लोगों से बातचीत करते थे। हालांकि, विभाग ने जांच की नवीनतम प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।



हुई। नोबेल समिति के मुताबिक, 96 वर्षीय कागन और 76 वर्षीय सोई को खोजों ने वैज्ञानिकों को असममित रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने, नियंत्रित करने और अधिक शुद्ध उत्पाद तैयार करने के नए उपकरण दिए हैं। साथ ही, इन खोजों ने यह समझने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि जीवन में पाए जाने वाली एकतरफा चिरैलिटी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। केंसो सोई टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से जुड़े हैं, जबकि कागन फ्रांस के यूनिवर्सिटी पेरिस-सूद से जुड़े हैं। हेनरी कागन ने 1986 में दिखाया कि असममित रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की संरचना और बनने वाले उत्पाद के बीच संबंध हमेशा सीधा या रैखिक नहीं होता। उन्होंने गैर-रैखिक प्रभाव की खोज की, जिसके माध्यम से किसी एक दर्पण-रूप के निर्माण को अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस खोज ने औषधियों, सुगंध, स्वाद और नई सामग्रियों के

नेपाल आपदा में लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण होगा आसान, संशोधित होंगे दो कानून

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशुली नदी क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा में लापता नागरिकों की मृत्यु दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार दो कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए ‘फास्ट ट्रैक’ प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गृह मंत्रालय के सचिव केदारनाथ शर्मा और कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्रालय के सहसचिव सुभाष भट्टराई ने भोटेकोशी-त्रिशुली आपदा संबंधी संसदीय विशेष समिति की सिंहदरबार में हुई बैठक में कहा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के कारण आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और अन्य कानूनी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए कानून में संशोधन आवश्यक है।

उनके अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पंजीकरण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कानून मंत्रालय प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। भट्टराई ने कहा कि वर्तमान में लापता नागरिकों की मृत्यु की घोषणा और मृत्यु पंजीकरण के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसलिए गृह मंत्रालय के समन्वय में संबंधित कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसे आवश्यकता के अनुसार फास्ट ट्रैक से आगे बढ़ाने की तैयारी है। भट्टराई ने बताया कि संसद का अधिवेशन नहीं होने की स्थिति में भी संशोधन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लापता नागरिकों की मृत्यु पंजीकरण की

नेपाल में भारत के आर्थिक सहयोग से बने विद्यालय भवन का मुख्यमंत्री कार्की ने किया उद्घाटन



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के मोरंग जिले की सुन्दरहर्षा नगरपालिका स्थित पंचायती माध्यमिक विद्यालय का नया भवन भारत सरकार ने निर्माण कराया है। इस भवन का उद्घाटन कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्मत कार्की, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव नारायण सिंह और सुन्दरहर्षा नगरपालिका के मेयर केदार प्रसाद गुरागाई ने संयुक्त रूप से किया। भारतीय दूतावास के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के तहत

किया गया है। दूतावास के अनुसार उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना शुरू होने के बाद से भारत सरकार ने नेपाल के सभी सातों प्रदेशों और 74 जिलों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कुल 605 परियोजनाएं संचालित की हैं। इनमें से 103 परियोजनाएं कोशी प्रदेश में हैं, जबकि अकेले मोरंग जिले में 17 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। भारत ने कोशी प्रदेश को 150 एम्बुलेंस और 62 स्कूल बसें भी उपलब्ध कराई हैं। इनमें मोरंग जिले को 21

पाकिस्तान ने वियना और जिनेवा में सिंधु जल संधि को बनाया मोहरा

वियना (ऑस्ट्रिया)। पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को मोहरा बनाते हुए भारत को घेरने की कोशिश की। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने तो वियना में इंटरनेशनल वॉटर सिम्पोजियम में भारत को गंभीर परिणाम की चेतावनी दे डाली। जिनेवा में सचिव (प्रथम) अदील मुमताज खोखर ने संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक दबाव बनाने के लिए पानी के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का कदम पानी को हथियार बनाने जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि साझा जल संसाधनों का इस्तेमाल दबाव डालने, राजनीतिक लाभ उठाने या युद्ध के लिए नहीं किया जाना चाहिए। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इशाक डार ने मंगलवार को वियना की डिप्लोमैटिक एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित इंटरनेशनल वॉटर सिम्पोजियम (अंतरराष्ट्रीय जल संगोष्ठी) में कहा कि सिंधु जल का हिस्सा न देने की किसी भी कोशिश के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डार ने कहा कि इस्लामाबाद को पता है कि उसे अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। उल्लेखनीय है

कि पिछले साल अप्रैल में भारत ने इस जल समझौते को स्थगित कर दिया था। यह कदम भारत ने कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उठाया था। इसके बाद मई 2025 में दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था। डार ने जोर देकर कहा कि सिंधु जल संधि और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प के बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ' सिंधु नदी का जल देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जindगी और रोजी-रोटी का जरिया है। पाकिस्तान के सचिव (प्रथम) खोखर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में पाकिस्तान का पक्ष रखा। परिषद सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकार पर एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। इस प्रस्ताव को जर्मनी और स्पेन ने पेश किया। इस प्रस्ताव को बिना मतदान के अपना लिया गया। खोखर ने कहा, 'जहां पानी साझा किया जाता है, वहां जिम्मेदारियां भी साझा होती हैं।' उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच साझा जल संसाधनों पर सहयोग कोई एहसान या रियायत का मामला नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है।



तत्काल समस्या के समाधान के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के दीर्घकालीन प्रभावों से निपटने के लिए भी कानूनी सुधार आवश्यक हैं। उनके अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने या आवश्यकता के अनुसार अलग से जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून बनाने के मुद्दे पर वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा मुलुकी देवानी संहिता

हूती विद्रोहियों का यमन अदन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन हमला

साना (यमन)। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के बंदरगाह शहर अदन के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर हमलाकर सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सामने नई चुनौती पेश की है। हूती विद्रोहियों ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आ पायी। मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि यह ‘डॉन ऑफ़ यमन’ ऑपरेशन के तहत ताइज के जबल हबाशी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया है। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि हूती के कब्जे वाली राजधानी सना और सादा व अमरान प्रांत, सऊदी अरब के खिलाफ हूती मिसाइल हमलों के मुख्य स्रोत हैं। यमन के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए हूती की निंदा की है। मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि यह ‘एक भयानक हमला’ है। हमले से यात्रियों, कर्मचारियों और फ्लाइट क्रू की जान को खतरा पैदा हो गया। मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मानवाधिकार मंत्रालय ने भी हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले की निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि एक मिसाइल एयरपोर्ट

के रन-वे के पास गिरी। इस वक्त काहिरा से यमेनिया एयरवेज की फ्लाइट 603 आम यात्रियों को लेकर वहां उतरने वाली थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस हमले से सऊदी शहर जेद्दा के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामने संकट खड़ा हो गया। मंत्रालय ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का ‘गंभीर उल्लंघन’ बताया। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले ने नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और आने-जाने की आजादी के अधिकारों का उल्लंघन किया है, साथ ही यात्रा, इलाज और देश लौटने के एक अहम रास्ते को भी खतरे में डाला है।

मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और नागरिक उड्डयन संस्थाओं से हमले की निंदा करने और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का आग्रह किया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ऐसे हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने की अपील भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार आप्रस्त से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच चल रही लड़ाई में लगभग 1,000 लोगों की मौत हुई है और 1,84,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हूती विद्रोहियों ने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर बाद में अपनी सरकार बना ली थी। इस बीच यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हंस ग्रंडबर्ग ने वाशिंगटन का अपना दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने यमन में हाल के घटनाक्रमों पर अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।

एक नजर

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन के निधन पर विभिन्न दलों ने जताया गहरा शोक

रांची,एजेंसी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर इंडी गठबंधन के अलावा विपक्षी दलों ने बुधवार को गहरा शोक प्रकट किया है। शोक प्रकट करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि दिवंगत रूपी सोरेन की आत्मा को मरांग बुरु को अपने निज धाम में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं जघपू के विधायक सरयू ने शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की। सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता के निधन की सूचना बेहद मर्माहत करने वाली है। उन्होंने एक सफल और सार्थक जीवन जिया और अपने पीछे भरा-पूरा परिवार और मातुवत् स्नेह पाने वाले हजारों लोगों की विरासत छोड़ी है। उन्होंने कहा कि दिवंगत माताजी का स्नेह और व्यक्तित्व हमेशा लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगा।

सरयू राय ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और समस्त परिजनों एवं समर्थकों को इस अपरूपीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। रूपी सोरेन के निधन पर प्रदेश कांग्रेस ने भी गहरा शोक जताया है। उनके निधन पर प्रदेश प्रधारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। के. राजू और केशव महतो कमलेश ने कहा कि रूपी सोरेन का निधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार के लिए अपरूपीय क्षति है। इस कठिन और दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। यधर, रूपी सोरेन के आकस्मिक निधन की सूचना पर प्रदेश राजद के नेताओं ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। उनके निधन की सूचना के बाद पार्टी की ओर से प्रस्तावित मशाल जुलूस एवं जिलों के घरखंड स्तरीय सभी कार्यक्रमों अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी प्रदेश राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव ने दी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव, श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, विधायक नरेश सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, पूर्व विधायक गौतम सागर राणा सहित अन्य, पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

दुर्गा पूजा से पहले रांची की 3.93 लाख महिलाओं के खाते में पहुंची मईयां सम्मान योजना की राशि

रांची,एजेंसी। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की तीन लाख 93 हजार 994 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में सितंबर 2026 की सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी गई है। प्रत्येक लाभुक के खाते में 2,500 रुपये की राशि आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई है। रांची जिले में योजना के तहत लाभुकों के खातों में कुल 98 करोड़ 49 लाख 85 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार की ओर से दुर्गा पूजा से पहले राशि का भुगतान किए जाने से महिलाओं और उनके परिवारों को त्योहार के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रखंड और शहरी क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार कांके में सबसे अधिक 31,483 लाभुकों को योजना की राशि मिली है। इसके बाद टाउन अर्बन क्षेत्रों में 25,893, मांघर में 22,936, सिल्ली में 21,269 और बेड़ो में 20,555 लाभुकों को भुगतान किया गया है। वहीं, कांके शहरी क्षेत्र में सबसे कम 1,281 लाभुकों को राशि मिली है। बुंदू नगर पंचायत में 3,558 और खलारी में 9,590 लाभुको के खातों में का सम्मान राशि भेजी गई है। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजन्ती ने भी कहा कि मईयां सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सितंबर माह की सम्मान राशि का समय पर भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ प्राप्त महिलाओं तक सीधे और सुगम तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सम्मान राशि का भुगतान महिलाओं और उनके परिवारों के लिए आर्थिक संबल देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं का केंद्र है मध्य प्रदेश : डॉ यादव

भोपाल,एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध वन्य जीव संपदा, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं का केंद्र है और राज्य सरकार पाददर्शी नीतियों, त्वरित अनुमतियों और सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार देश शाम भोपाल में आयोजित ‘एमपी ट्रेवल मार्ट : 2026’ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने और निजी निवेश को गति प्रदान करने के उद्देश्य से देश-विदेश के प्रमुख पर्यटन निवेशकों, हॉस्पिटैलिटी समूहों और स्पेकहोल्डर्स के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना, धरोहर संरक्षण, कौशल विकास, फिल्म पर्यटन और विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया तथा निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) प्रदान किए गए।

निवेश संवर्धन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सीहोर जिले के रामगढ़ में ए.आर.एम. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 848.40 करोड़ रुपये के निजी निवेश से गोल्फ कोर्स, होटल विला, वेलेन्स रिसॉर्ट एवं लकजरी होटल परियोजनाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण एमओयू किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में 920 प्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर ए.आर.एम. फूड्स का प्रतिनिधित्व कंपनी के



चेयरमैन एवं निदेशक श्री अतुल अग्रवाल ने किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निवेशकों, संस्थाओं और उद्यमियों का स्वागत करते हुए आश्चस्त किया कि राज्य सरकार भूमि आवंटन, अधोसंरचना विकास और आवश्यक स्वीकृतियों को समयबद्ध रूप से पूरा करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन महत्वपूर्ण एमओयू, निवेश प्रस्तावों और लेटर ऑफ अवॉर्ड के माध्यम से मध्यप्रदेश का पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। पर्यटन विकास, योजना और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण एमओयू भी हुए। फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में एसीएडी, इंदौर के साथ फिल्म निर्माण शिक्षा, पर्यटन एवं कंटेंट निर्माण के लिए

समझौता (एमओयू) हुआ। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के तहत स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली के साथ ओरछा के ऐतिहासिक परिसर की समेकित प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एमओयू हुआ। कौशल विकास अन्तर्गत भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), रवालियर के साथ पर्यटक वाहन चालकों के आरपीएल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के लिए एमओयू किया गया। इसके प्रथम चरण में भोपाल के 100 पर्यटक वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें संस्थान का प्रतिनिधित्व प्रो. प्रशांत के. गौता ने किया। वहीं, द्रोणह के साथ ओरछा परिसर के पर्यावरण, लैंडस्केप एवं संरक्षण योजना तैयार करने के लिए एमओयू किया

गया, जिसमें श्रीमती शिखा जैन ने प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त, टेकनपुर (रवालियर) में स्थित बीएसएफ अकादमी में पर्यटन सुविधाओं के विकास, डिजिटल अधोसंरचना और बीएसएफ म्यूजियम के उन्नयन के लिए बीएसएफ अकादमी, एमपीएसटीडीसी तथा जिला प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व डीआईजी हरिंदर सिंह तोमर एवं रितेश ठाकुर ने किया।

वन-टू-वन बैठकों के दौरान हॉस्पिटैलिटी और लकजरी रिसॉर्ट्स के क्षेत्र में अन्य बड़े निवेश प्रस्ताव भी सामने आए। एटमॉस्फियर ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री सीभाग्य महापात्रा ने उज्जैन, इंदौर और प्रमुख वन्य जीव सर्किटों में लकजरी हॉस्पिटैलिटी विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना साझा की। रेनी ग्रुप के निदेशक पंकज फुलवानी ने मांडू में 350 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक लुनेरा सराय को ‘वेलकम होटल बाय आईटीसी’ (130 करोड़ रुपये) के रूप में विकसित करने, खजुराहो में कुटनी डैम के सामने वॉटर फ्रंट रिसॉर्ट (125 करोड़ रुपये), सीधी में ‘स्टोरी लाय बीय आईटीसी’ (35 करोड़ रुपये) और मैहर में बाणसागर डैम के पास रिसॉर्ट सहित कुल 290 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के संबंध में चर्चा हुई। सर्व ग्रुप के प्रबंध निदेशक कुणाल ज्ञानी ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (महई) में ‘ताज सफारीज’ के साथ 40 एकड़ में 100 करोड़ रुपये के अल्ट्रा-लकजरी वन्य जीव रिसॉर्ट और राज्य में कुल 300 करोड़ रुपये के समग्र निवेश संबंधी चर्चा की।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं का योगदान अहम : संजय सरावगी

पटना। बिहार भाजपा एनआरआई सेल के तत्वावधान में बुधवार को पटना के होटल लेमन ट्री, एनजीबिशन रोड में सपनों का भारत 2047 कॉन्क्लेव के तहत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिन्हा ने की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं और युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिन्हा द्वारा स्वागत किया गया। युवाओं को सम्बोधित करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक दायित्व के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके संवैधानिक दायित्व के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जनता हैं, जिनकी नीतियों और सिद्धांतों में हमेशा यह प्राथमिकता रही है कि भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। पिछले 25 वर्षों की जनसेवा



में उन्होंने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि युवा केवल जांब सोकर नहीं, बल्कि जांब गिबर बनें। इसी तरह युवा केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजर न रहें, बल्कि एआई के क्रिएटर, इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर भी बनें।

उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में युवा नए अवसरों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा, उद्यमी, गरीब, किसान, श्रमिक और ईडब्ल्यूएस लाभार्थी सहित समाज के हर वर्ग के विकास को

प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता दी है। भारत आज तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों क्षेत्रों में देश आगे बढ़ रहा है। संजय सरावगी ने कहा कि 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब उसके निर्माण में देश के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। युवाओं के सपनों, नवाचार और ऊर्जा को सही दिशा मिलना विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। उन्होंने युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, युवा उद्यमी और अन्य लोग उपस्थित रहे।

सम्राट हेमू की जयंती पर उठा इतिहास में उचित स्थान देने का मुद्दा, पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग

नई दिल्ली,एजेंसी। रौनियार वैश्य सभा, दिल्ली (रजि.) के तत्वावधान में मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन में वीर योद्धा एवं राष्ट्रनायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ‘हेमू’ की जयंती और विजयोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में असम और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी मुख्य अतिथि तथा लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ अतुल सिंघल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वक्ताओं ने सम्राट हेमू के जीवन, सैन्य उपलब्धियों और योगदान को इतिहास की पुस्तकों में प्रमुखता से शामिल करने की आवश्यकता जताई। प्रो. जगदीश मुखी ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे योद्धा का इतिहास समाज और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर हेमू ने तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वोच्च सत्ता तक अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हेमू के जीवन में 22 युद्धों में विजय प्राप्त करने का दावा करते हुए उनके सैन्य कौशल को रेखांकित किया।

पानीपत की दूसरी लड़ाई का उल्लेख करते हुए मुखी ने कहा कि हेमू की पराजय ने इतिहास की दिशा को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में कई ऐसे योद्धा रहे हैं, जिनके योगदान का अपेक्षित मूल्यांकन नहीं हो सका। मुखी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ में हेमू का उल्लेख किए जाने के बाद उनके इतिहास को लेकर चर्चा बढ़ी है। उन्होंने शोधकर्ताओं से हेमू के जीवन और संघर्ष पर तथ्यपरक अध्ययन करने



का आह्वान किया। डॉ अतुल सिंघल ने कहा कि मुख्यधारा के इतिहास में लचित बरफुकन समेत अनेक राष्ट्रनायकों के योगदान को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। उन्होंने सम्राट हेमू को भी ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में शामिल बताया, जिनके सैन्य कौशल और राजनीतिक उपलब्धियों का विस्तृत अध्ययन नई पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के ऐसे योद्धाओं के इतिहास को सामने लाने की जरूरत है, जिनके योगदान पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। डॉ. सिंघल ने घोषणा की कि वह अपनी आगामी पुस्तक में सम्राट

हेमू के शौर्य, संघर्ष और जीवन से संबंधित प्रामाणिक सामग्री को शामिल करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक एवं मीडिया प्रभारी पंकज रौनियार ने सासाराम में सम्राट हेमू की भव्य आदमकद प्रतिमा स्थापित करने, दिल्ली के लुटियंस जोन में किसी प्रमुख मार्ग का नाम उनके नाम पर रखने और स्कूली पाठ्यक्रम में उनके योगदान को विस्तार से शामिल करने की मांग रखी। प्रो. मुखी ने इन मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वे सम्राट हेमू से जुड़े प्रस्तावों को उचित स्तर पर सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे।

देश को विकसित बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प देखे हैं उनको सभी कार्यकर्ता गांवों तक लेकर जाएं : नितिन नबीन

वाराणसी,एजेंसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के रोहनिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से आयोजित ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ के समापन पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह यात्रा उनके जन्मस्थान वडनगर (गुजरात) से शुरू होकर उनकी कर्मभूमि काशी पहुंची है। समापन कार्यक्रम और जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद नितिन नबीन, असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए। जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सेवा संकल्प अभियान के सत्र को संबोधित करने के साथ लगभग 20 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वाराणसी पहुंचे बाइकर्स का स्वागत किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने में प्रधानमंत्री ने जो संकल्प देखे हैं उनको सभी कार्यकर्ता गांवों तक लेकर जाएं। नितिन नबीन ने कहा कि इतिहास का निर्माता ऐसे नहीं बनता बल्कि अगर हम पिछले 25 वर्षों देखें तब हम जरूर कह सकते हैं की देश के प्रधानमंत्री ने इतिहास रचा है। जनभावना को समझते हुए उन्होंने देश को गिराशा के माहौल से निकालने का कार्य किया। उन्होंने युवाओ के अंदर आशा और उम्मीद को जगाने का कार्य किया है। उन्होंने तीन तलाक, विषय की चौथी अर्थव्यवस्था बनाने, सभी व्यक्तियों को छत देकर चार करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया, नक्सलवाद को खत्म किया, उत्तर पूर्व रण्यों तक



आसान पहुंच सुनिश्चित की, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में प्रदेश आगे बढ़ा ये सभी विकास कार्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के प्रयासों से हुआ है। उन्होंने पं.दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की भी बात की। उन्होंने विषय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विषय देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाना चाहता हैं। अराजकता वादी मानसिकता को भारत की जनता जवाब देगी। ‘वो कैन डूइड’ नारे के साथ युवा सभी जगहों पर डटा रहेगा। युवा साथी न थकेगा न टिकेगा 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ेगा।

जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन भारत माता की जय, वंदे मातरम्, हर हर महादेव के नारे के साथ किया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन तवीन का काशी की पावन धरा पर काशीवासियों की तरफ से स्वागत किया। सुरक्षित एवं विकसित असम के लिए हिमंत बिस्वा सरमा का भी स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के हेड ऑफ स्टेट के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर यात्रा के काशी में आगमन पर हार्दिक बधाइयां एवं

शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पहले गुजरात की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री ने प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर लाकर खड़ा किया।

पिछले वर्षों में काशी को बदलते देखा गया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, जमीन पर अवैध कब्जा, महिलाओं के साथ खिलवाड़, अराजकता चरम पर थी लेकिन आज माफिया मिट्टी में मिला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ धाम अपने नए स्वरूप में आगे आया, मां विंध्यवासिनी का भव्य कारीडोर बना, दिव्य और भव्य कुंभ भी बना। आज उत्तर प्रदेश एक नए आयाम स्थापित किया है। सेवा संकल्प अभियान प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यात्रा में शामिल युवाओं व कार्यकर्ताओं के साहस और निष्ठा की सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वडनगर से काशी तक का यह मार्ग चुनौतीपूर्ण था और सुस्का को लेकर प्रारंभिक चिंताएं थीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के अटूट संकल्प और उत्साह के सामने हर बाधा आसान हो गई।